HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 नवम्बर, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 2/ अंक 32/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

दिये की याद अंधेरे में ही आती है,गुणी व्यक्ति को कष्ट में याद किया जाता है ..... डॉ0 एल सी शर्मा

सैंकड़ो युवाओं को रोजगार आधारित प्रशिक्षण देगा आईआईआरडी

हिमाचल में एनएसडीसी और उत्तराखंड में डीडीयूजीकेवाई के तहत युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण

उत्तरप्रदेश में तीन सौ से अधिक ने प्रशिक्षण के साथ पाया रोजगार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के गुर सिखाकर उन्हें रोजगार व से जोड़ने में एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) शिमला लंबे समय से काम कर रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हिमाचल, उत्तराखंड में आईआईआरडी ने एक और अहम पहल की है। इसके तहत आईआईआरडी हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (कौशल विकास निगम) के साथ मिलकर सीएसआर कौशल विकास प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने की योजना बना रहा है वहीं उत्तराखंड में दीनदयालउपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयूजीकेवाई) के तहत युवाओं को कौशल विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे पहले डीडीयूजीकेवाई के तहत उत्तरप्रदेश में 380 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और करीब 300 की प्लेसमेंट भी की जा चुकी है। बाकियों को रोजगार मुहैया कराने की प्रक्रिया जारी है।

डीडीयूजीकेवाई के तहत उत्तराखंड में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय व उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से आईआईआरडी द्वारा में डीडीयूजीकेवाई के तहत तीन जिलों के बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तकाशी में रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का कार्य शुरू हो चुका है। इस केंद्र में 300 युवाओं को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी अकांऊट एसिस्टेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केंद्र में उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और रूद्रप्रयाग से 100–100 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रमाण पत्र और सुनिश्चित रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे जिसमें न्यूनतम 10 से 12 हजार से शुरूआती वेतन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में शिमला सुन्नी, रामपुर और हमीरपुर व उत्तराखंड में उत्तरकाशी और चमोली तथा बिहार के बक्सर में विभिन्न एसएससी सर्टीफाइड जॉब रोल में प्रशिक्षण देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

कौशल विकास के पथ पर आईआईआरडी के लक्ष्य

- प्रदेश ही नहीं देश में 100 फीसदी कौशल विकास का लक्ष्य प्राप्त करना
- निजी क्षेत्र में एक ऐसे कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करना जहां से कौशल में कुशल उद्यमियों को तैयार किया जा सके
- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की 100 फीसदी प्लेसमेंट करना
- सरकार की योजना का लाभ हर गांव–हर गांव तक पहुंचाकर ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना
- अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों की उद्यम क्षमता की पहचान कर उनकी क्षमतानुसार कौशल संवर्द्धन करना
- नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना
- कम जोखिम में अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना
- उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना
- सर्वांगीण विकास में सहयोग करना
- भविष्य के लिए बेहतर योजना तैयार करने में सहयोग करना

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का महत्व

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। आजीविका गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है। इस योजना से 550 लाख से अधिक ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को जो कुशल होने के लिए तैयार हैं, स्थायी रोजगार प्रदान करने के द्वारा लाभ होगा। इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation @ NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल

विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008–09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी।

सुन्नी में शुरु हुआ पीएमकेवीवाई केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के युवाओं का हुनर तराशन के लिए आईआईआरडी की ओर से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साझेदार के तौर पर पीएमकेवीवाई केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर युवाओं के कौशल को तराशने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में शिमला के सुन्नी में हाल ही में केंद्र शुरू हो चुका है। इस केंद्र पर 60 युवाओं को रिटेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 30 बच्चों को बैच शुरू हो चुका है। जल्द ही रामपुर और रोहड़ू में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र खोले जाने की योजना है। यह प्रशिक्षण करीब तीन सौ घंटों का होगा और इसके लिए केंद्र में कंप्यूटर लैब खास तौर पर स्थापित की गई है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षार्थियों की नियम और शर्तों के मुताबिक प्लेसमेंट भी की जाएगी।

देश दुनिया समाचार

महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर हो रही खींचतान

महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी शिवसेना के बीच लंबे समय तक तल्खी का माहौल बना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीजेपी शिवसेना को कैबिनेट में 14 सीटें देना चाहती है, लेकिन शिवसेना 18 सीटों की मांग करती रही। इसके अलावा, शिवसेना महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर भी दावेदारी ठोंक रही। जबकि मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि वे गृह और शहरी विकास जैसे प्रमुख मंत्रालयों का बंटवारा नहीं करेंगे।

बीजेपी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अगर शिवसेना चाहे तो अपने किसी नेता को डिप्टी सीएम जैसे अहम पद पर भी बैठा सकती है। लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक खींचतान जारी रही।

वर्ष 2019 के चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के लिए नतीजे कुछ खास उत्साहजनक नहीं रहे। बीजेपी-शिवसेना गठबंधन फिर से सरकार बनाने की स्थिति में तो थी लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर उलझी रही। प्रमुख दलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 सीटें मिली है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने 56 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं कांग्रेस 44 सीटें अपने नाम कर चुकी है। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं।

खट्टर ने फिर संभाली हरियाणा की कमान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार निर्मित करने का निर्णय लिया है। मनोहर लाल खट्टर पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गये हैं, उन्होंने 27 अक्तूबर को दिवाली पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनता जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले 24 अक्टूबर, 2019 को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के परिणामों की घोषणा की गयी थी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। परन्तु भाजपा बहुत हासिल करने से चूक गयी थी।

90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 40 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 31 सीटें प्राप्त हुई हैं। जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी को एक सीट पर जीत प्राप्त हुई है। इंडियन नेशनल लोक दल को भी एक सीट प्राप्त हुई है।

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का सरगना बगदादी मारा गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 27 अक्तूबर 2019 को औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल-बगदादी मारा जा चुका है। ट्रम्प ने एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के स्पेशल कमांडोज ने सीरियाई प्रान्त इदलिब के सुदूर गाँव बारिशा में एक विशेष अभियान के तहत बगदादी को मार गिराया है।डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब बगदादी पूरी तरह से अमेरिकी सेना से घिर गया तो उसने स्वयं को आत्मघाती बम से उड़ा लिया।

इस तरह वह भी उसी प्रकार से अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारा गया जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया था।

जस्टिस एस ए बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्तूबर 2019 को जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (एस ए बोबडे) को देश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वे 18 नवंबर को भारत के नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

राष्ट्रपति के इस निर्णय से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नियमानुसार जस्टिस बोबडे को अगला मुख्य न्यायधीश बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पारित कर दिया गया है। गौरतलब है कि रामजन्म भूमि मामले में सुनवाई कर रहे पांच जजों की पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे भी शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी उज्जैन को स्वच्छ बनाने में आईआईआरडी का योगदान

गेल इण्डिया के साथ मिलकर पूरा हुआ सुपोर्ट टूवर्ड प्रोवाइडिंग पब्लिक गारबेज बिन्स प्रोजेक्ट

चंडीगढ़-बंगलूरु में लगाए जा चुके हैं एक हजार गारबेज बिन

द रीव टाइम्स

भारत को साफ और स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2 अक्तूबर 2014 को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की थी। आईआईआरडी शिमला इस स्वच्छ भारत अभियान को अनोखे और सराहनीय तरीके से आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईआईआरडी गेल इंडिया के सहयोग से सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत अलग-अलग प्रदेशों में नगर निगम के साथ मिलकर इस अभियान को आगे ले जा रहा है। सुपोर्ट टूवर्ड प्रोवाइडिंग पब्लिक गारबेज बिन्स के तहत आईआईआरडी की ओर से शहरों में अतिआधुनिक और सुरक्षित कूड़ा दानपात्र प्रदान किए जा रहे हैं। यह कूड़ादान शहरों की जरूरत के हिसाब से खासतौर पर तैयार किए गए हैं। इन कूड़ेदानों की खासियत यह है कि इन्हें स्टील से तैयार किया गया है। इसमें गीला और सूखा कूड़ा डालने के लिए अलग -अलग बॉक्स बनाए गए हैं।

कूड़ेदान उपलब्ध कराने के साथ ही आईआईआरडी की ओर से लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग रखने और उन्हें गारबेज क्लेक्टर (कूड़ा एकत्र करने वाले) को देने के लिए विशेष तौर पर जागरूक किया जा रहा है। कूड़े को कूड़ा संयत्र पर ट्रीट करने में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब संयत्र पर कूड़ा अलग -अलग कर नहीं पहुंचता। अक्सर घरों पर सभी तरह का कूड़ा एक साथ एक ही डस्टबिन में डाला जाता है। गीला-सूखा, यहां तक की धातुओं से बनी वस्तुएं भी सामान्य कूड़े के साथ मिक्स की जाती है। ऐसे में कूड़े को ठिकाने लगाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कूड़े का सही निस्तारण न होने के कारण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आईआईआरडी की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही गारेबेज का वितरण भी किया जा रहा है।

बंगलूरु और चंडीगढ़ में सफल रहा अभियान

अभी तक आईआईआरडी की ओर से बंगलूरू और चंडीगढ़ में गारबेज बिन का वितरण किया जा चुका है। यह प्रोजेक्ट 2018 में पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ में 400 और बंगलूरू में 600 गारबेज का वितरण किया जा चुका है। यह पूरी तरह से सफल रहा है। यहां पर अब 90 फीसदी लोग इन गारबेज बिन में गीला सूखा कूड़ा अलग डालते हैं। इतना ही नहीं धातुओं से बनी वस्तुओं को मेगनेट यानि चुंबक ही सहायता से अलग किया जाता है। इन गारबेज में इस प्रक्रिया को अंजाम देना साधारण कूड़ेदानों के मुकाबले काफी आसान और सुरक्षित है। इसलिए अब लगातार दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह के गारबेज लगाने की मांग बढ़ रही है।

उज्जैन में भी पूरा हुआ प्रोजेक्ट

चंडीगढ़ और बंगलूरू में सुपोर्ट टूवर्ड प्रोवाइडिंग पब्लिक गारबेज बिन्स प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के बाद अब उज्जैन में गारबेज बिन का पूरा हुआ काम । इसके लिए एमओयू साइन करने के साथ ही तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी की गई । पहले चरण में उज्जैन नगर निगम को 60 गारबेज बिन प्रदान किए गए । 60 लीटर की कैपेस्टी वाले ये गारबेज बिन स्टील से बने हुए है। गीले-सूखे कूड़े के लिए एक साथ दो बिन को अटैच किया गया है।

बंदरों और अन्य जानवरों से सुरक्षा

साधारण कूड़ेदानों के पास अक्सर बंदरों और कुत्तों समेत अन्य जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। कारण ये कि इन कूड़ेदानों से कूड़ा अक्सर इधर-उधर बिखर जाता है लेकिन आईआईआरडी की ओर से जो गारबेज बिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह इस लिहाज से काफी सुरक्षित और साफ-सुथरे हैं।

स्वच्छ भारत के लिये क्यों जरुरी है कचरा प्रबंधन

आज कचरे का प्रबन्धन, पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण समय की माँग है। हमारे गाँव और शहरों में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर और उनमें पनपते रोग आज गम्भीर खतरा बन चुके हैं। घर से कार्यालय या कहलेज जाते समय और ट्रेन से किसी रेलवे स्टेशन पहुँचने से पूर्व नजर आते कचरे के पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। कचरे में स्थानीय मवेशी प्लास्टिक की पन्नियों को अपना भोजन बनाते हैं तो कहीं सड़े-गले कचरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी इनके पेट में चला जाता है। ऐसे में आज कचरे का प्रबन्धन, पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण समय की माँग है।

एक अनुमान के अनुसार भारत के 7935 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 37 करोड़ 70 लाख निवासियों के कारण प्रतिदिन 1,70,000 टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जब शहरों में 59 करोड़ नागरिक हो जाएँगे और आबादी बढ़ने से शहरों की सीमाएँ समाप्त हो जाएँगी तो प्राकृतिक शहरी अपशिष्ट का प्रबन्धन करना मुश्किल होगा।

स्वच्छ भारत अभियान पर गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह ने वर्ष 2015 की रिपोर्ट में अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्रों की सिफारिश की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि कूड़े का सही और वैज्ञानिक निस्तारण हो, जिसकी शुरूआत घरों से कूड़ेदान में कूड़ा पहुंचने के तरीके से शुरू हो जाती है।

आज अपशिष्ट की समस्या इतनी गहरी है कि उसके दहन से जहरीली गैसों के फैलने की आशंका है क्योंकि अपशिष्ट में सड़ा-गला भोजन, पन्नियाँ, प्लास्टिक व धातु का कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा सभी कुछ शामिल होता है, जिसके संयंत्र में दहन करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आज अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की कई तकनीकों का विकास किया गया है जो पहले से अधिक स्वच्छ और अधिक किफायती ऊर्जा उत्पादन के लिये अपशिष्ट का प्रसंस्करण करती हैं, जिसमें शामिल हैं लैंडफिल गैस अवशोषण, थर्मल पाइरोलिसिस और प्लाज्मा गैसीकरण। पुराने अपशिष्ट भट्ठी संयंत्र, उच्च-स्तरीय प्रदूषकों का उत्सर्जन करते थे, जबकि आज थर्मल पाइरोलिसिस और प्लाज्मा गैसीकरण जैसी नई प्रौद्योगिकियों ने दहन से प्रदूषण की चिन्ता को काफी कम कर दिया है। नीति आयोग ने थर्मल पाइरोलिसिस और प्लाज्मा गैसीकरण प्रौद्योगिकियों के लाभ व लागत के आनुपातिक मूल्यांकन भी किये हैं। ये अधिक बजट वाली तकनीकें हैं जिन पर राज्यों का समर्थन आवश्यक है। अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद और बायोगैस उत्पन्न करने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे राज्यों की मदद से ही हासिल किया जा सकता है। अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण में रोजगार सृजन की भी प्रबल सम्भावनाएँ हैं, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्लास्टिक का अपशिष्ट प्रबन्धन एक चुनौती

प्लास्टिक व पॉलीथिन आज अपशिष्ट प्रबन्धन में एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक व पॉलिथीन को किसी भी प्रक्रिया से नष्ट नहीं किया जा सकता और जानवर कचरे में पड़े भोजन के साथ पन्नियों को खाकर अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की मौतें पॉलिथीन के कचरे को खाकर होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 30–40 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। हर साल करीब साढ़े सात लाख टन पॉलिथीन कचरे की रिसाइक्लिंग की जाती है और बाकी पॉलिथीन नदी, नाले और मिट्टी में जमा रहते हैं और संकट का सबब बनते हैं। प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएँ कचरा प्रबन्धन प्रणालियों की खामियों की वजह से पैदा हुई हैं। प्लास्टिक का यह कचरा नालियों और सीवेज व्यवस्था को ठप कर देता है। नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है। रिसाइकिल किये गए या रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो जमीन में पहुँच जाते हैं और इससे मिट्टी एवं भूजल विषैला बन सकता है।

गेल
GAIL
गेल (इंडिया) लिमिटेड सी एस आर कार्यक्रम के अंतर्गत
IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Implemented by: IIRD – www.iirdshimla.org
Institute for Integrated Rural Development
एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइक्लिंग इकाइयाँ नहीं लगी होतीं उनमें रिसाइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले जहरीले धुएँ से वायु प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुलमिल नहीं सकता। इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाये तो यह भूजल की रिचार्जिंग को रोक सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिये और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों, रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिये किया जाता है। इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसी धातुएँ स्वास्थ्य के लिये बेहद नुकसानदायक हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं और दिल का आकार बढ़ सकता है। लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है। प्लास्टिक के कुछ घटकों जैसे बेंजीन और विनाएल क्लोराइड को कैंसर का कारण जाना जाता है और तरल हाइड्रोकार्बन पृथ्वी और हवा को दूषित करते हैं। प्लास्टिक के उत्पादन के दौरान कुछ कृत्रिम रसायन जैसे एथिलीन ऑक्साइड, बेंजीन और

जाइलींस उत्सर्जित होते हैं जो पारिस्थितिकी प्रणाली को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुँचाते हैं तथा रक्त और गुर्दों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आज आप हर गली-चौराहे पर लोगों को पॉलिथीन में गर्म चाय और भोजन ले जाता देख सकते हैं जो विषाक्त हो जाता है। इतना ही नहीं प्लास्टिक की बोतलों में पैक मिनरल वॉटर भी ट्रकों में चलकर धूप की गर्मी में लगातार प्लास्टिक के सम्पर्क में रहकर विषाक्त हो सकता है, जिसके कई वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं। पॉलिएथिलीन, पॉलिविनाएल क्लोराइड, पॉलिस्टरीन बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सिंथेटिक पॉलिमर आसानी से जटिल आकार में ढल जाते हैं। ये उच्च रासायनिक प्रतिरोधक हैं और अधिक या कम लोचदार होते हैं। कुछ को फाइबर या पतली पारदर्शी फिल्मों में भी बदला जा सकता है। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें कई लोकप्रिय, टिकाऊ या डिस्पोजेबल वस्तुओं और पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिये उपयोग में लाया जाता है। अत्यधिक आण्विक आकार होने के कारण ही इन रसायनों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और ये लम्बे समय के लिये मिट्टी के वातावरण में अपने आप को बनाए रखते हैं।

यौन उत्पीड़न का आरोपित शिक्षक सस्पेंड

द रीव टाइम्स

रोहड़ू के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आठ छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले के आरोपित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक संजय देष्टा को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन (निलंबन) के दौरान उसका मुख्यालय क्षेत्र के ही एक अन्य स्कूल में निर्धारित किया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि वह अपने स्कूल में मामले से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके।

उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। विभागीय जांच का जिम्मा उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा) राजेश्वरी को सौंपा गया है। वह एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को सौंपेंगी। अभी महकमे ने यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। यह रिपोर्ट स्कूल प्रशासन के माध्यम से उपनिदेशक के पास भेजी गई थी। इसे 26 अक्टूबर को निदेशालय भेजा गया था। इसमें आरोपित शिक्षक पर आरोपों की पुष्टि हो गई है। अब अगर विभागीय जांच में भी आरोप सही पाए गए तो संजय देष्टा को सरकार नौकरी से भी बर्खास्त कर सकती है।

खूंखार तेंदुए ने घर के बाहर बैठे कुत्ते का किया शिकार

द रीव टाइम्स

हिमाचल प्रदेश की राजधानी और टूरिस्टों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक शिमला में इन दिनों तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने वहां के लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। शिमला के शनान इलाके में शुक्रवार तड़के तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। सुबह चार बजे के करीब कुत्ता घर के बाहर दरवाजे पर सोया हुआ था। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आई तो घर के लोग दरवाजा खोल बाहर निकले लेकिन, तब तक तेंदुआ कुत्ते को खींचकर ले जा चुका था। लोगों में दहशत है कि तेंदुआ इलाके में आ चुका है और कभी भी किसी पर कहीं भी हमला कर सकता है।

सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तेंदुआ कुत्ते के पास कुछ मिनट खड़ा रहा । इसके बाद अचानक हमला कर उसे गले से पकड़कर ले गया । इससे पहले भी इस इलाके में लोगों को तेंदुए नजर आए है, जिससे लोग डरे हुए हैं। जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि सीसीटीवी का जो फुटेज सामने आया है उसकी जांच की जा रही है। जंगल से सटा होने के कारण यहां तेंदुए आते रहते हैं।

छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक पर विभागीय जांच, उच्च निदेशालय को सौंपेंगे रिपोर्ट

द रीव टाइम्स

जिला शिमला के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले के आरोपी शिक्षक पर विभागीय जांच की जाएगी। उपनिदेशक कार्यालय ने प्रधानाचार्य स्तर की महिला अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। साथ ही मामले की जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा गया है। महिला जांच अधिकारी वीरवार को स्कूल में जाकर अपनी जांच शुरू करेंगी। जांच अधिकारी इस दौरान शिकायतकर्ता छात्राओं, प्रधानाचार्य और शिक्षकों से भी मामले को लेकर पूछताछ करेंगी।

इसके लिए अलग-अलग प्रश्नावली बनाई गई है। इसमें शिक्षक के खिलाफ आरोप लगाकर शिकायत करने वाली छात्राओं से भी जांच अधिकारी अलग से बातचीत कर आरोपों की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगी। शिक्षक पर लगे गंभीर आरोपों के बाद स्कूल स्तर पर बनी सेक्सुअल ह्यसमेंट कमेटी के सदस्यों के अलावा स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। तीन दिन में उप निदेशक कार्यालय स्तर पर बैठाई गई यह जांच पूरी करने को समय सीमा तय की गई है। रिपोर्ट को उप निदेशक निदेशालय को आगामी कार्रवाई के लिए सौंपेगी।

गंभीर हुई सरकार, मोदी के सुझावों पर मंथन शुरु

द रीव टाइम्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए दिए गए निवेश से संबंधित सुझावों पर मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव डह. श्रीकांत बाल्दी ने अधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं । प्रधानमंत्री ने डह. श्रीकांत बाल्दी व अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार को पर्यटन, निर्माण, कौशल विकास, आयुर्वेद, बागवानी तथा अन्य उद्योग आधारित स्थानीय संसाधनों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के विकास पर जोर देने का सुझाव दिया था । अब सरकार इन क्षेत्रों को लेकर गंभीर हुई है। अब बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करेंगे। वह मोदी के सुझावों पर अधिकारियों को निर्देश देंगे। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बैकड्राप का डिजाइन फाइनल होगा। सात व आठ नवंबर को धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इनवेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव ने इसके लिए उद्योग और आइटी विभाग को निर्देश दिए हैं।

महानाटी से किन्नौर महोत्सव का आगाज

द रीव टाइम्स

रिकांगपिओ के रामलीला मैदान में सूरत नेगी ने किया शुभारंभ प्रदर्शनियां निहारी, उपायुक्त ने किया चीफ गेस्ट का स्वागत

रिकांगपिओ दूराज्य स्तरीय चार दिवसीय किन्नौर महोत्सव का शुभारंभ रिकांगपिओ के राम लीला मैदान में सूरत नेगी, उपाध्यक्ष वन निगम हि.प्र. ने महोत्सव का झंडा फहरा कर व द्वीप प्रज्जवित कर किया।

हिमाचल में पटवारियों के 1194 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन होगा टेस्ट, डेट जारी

द रीव टाइम्स

हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 1194 पदों पर भर्ती प्रकिया के तहत 17 नवंबर को लिखित परीक्षा होगी । 17 नवंबर को सुबह 11 से 12.30 बजे तक परीक्षा करवाई जाएगी। इसके सभी जिलों के डीसी को एग्जामिनेशन सेंटर बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। गौरतलब है कि जिला लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में पटवारियों के पद भरे जाएंगे । इनमें मोहाल के तहत 932 और सेटलमेंट में 262 पद भरे जाएंगे ।

नकल रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध

हिमाचल में हाल ही में पुलिस भर्ती की परीक्षा के दौरान पालमपुर में हाईटैक नकल का पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध रहेंगे । इस बाबत सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं ।

ढाई लाख आवेदन आए

1194 पदों के लिए सूबेभर से ढाई लाख आवेदन आए हैं। करीब 300 आवेदन रद्द हुए हैं। जिला स्तर पर यह आवेदन मांगे गए थे। अब डेढ़ घंटे की परीक्षा आयोजित होगी । परीक्षा केंद्र बनाने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों के निर्देश दे दिए हैं । हिमाचल में बिलासपुर में 31, चंबा में 68, हमीरपुर में 80, कांगड़ा 220, किन्नौर 19, कुल्लू में 42, मंडी 174, शिमला में 115 सिरमौर में 52 सोलन में 63, ऊना में 69 पटवारियों के पद भरे जाएंगे। कांगड़ा मंडल में 143 और शिमला मंडल में 119 पटवारियों के पद भर जाएंगे ।

एचपीयू के दो दिव्यांग विद्यार्थियों का पीएचडी में दाखिला

द रीव टाइम्स

एचपीयू के दो दिव्यांग विद्यार्थियों ने पहले जेआरएफ की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की और अब इसी आधार पर पीएचडी में प्रवेश पा लिया है । सवीना और अजय कुमार ने जेआरएफ के आधार पर क्रमशः हिंदी और इतिहास विभाग में पीएचडी में प्रवेश लिया है । दोनों का सपना है कि वे अपनी पीएचडी पूरी कर प्रोफेसर बनें । विवि के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्र और छात्राओं को सुविधाएं प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करने का प्रयास कर रहा है। विवि के विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी ने बताया कि जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) परीक्षा पास करने वाली सवीना शारीरिक रूप से अक्षम है। अजय कुमार दृष्टि बाधित है। सवीना ने इससे पूर्व हिंदी में एमए, एमफिल के अलावा बीएड की है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र पढ़ चुकी हैं और मूलतः रोहड़ू की रहने वाली हैं। दृष्टिबाधित अजय कुमार विवि सुगम्य लाइब्रेरी में कंप्यूटर पर टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं।

हिमाचल के 11 शहरों का हाल : दीवाली पर शिमला, धर्मशाला सहित इन शहरों में बढ़ा पोल्यूशन

द रीव टाइम्स

दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है । यहां पर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, दीपावली पर हिमाचल में प्रदूषण का स्तर आम दिनों के मुकाबले बढ़ा है । सूबे के 11 शहरों में दिवाली के दिन और बाद प्रदूषण के स्तर को लेकर हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से आंकड़े सामने आए हैं। हिमाचल में ग्रीन दीवाली मनाने की अपील का लोगों पर 60 फीसदी असर देखने को मिला है। सूबे के 11 शहरों में से छह पोल्यूशन लेवल आम दिन के मुकाबला बढ़ा है । इन 7 शहरों में आरएसपीएम का स्तर 100 से अधिक रहा है । इसके अलावा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर गिरा है ।

11 शहरों का आंकलन

दरअसल, हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से दिवाली के अगले दिन का प्रदूषण स्तर का डाटा जुटाया गया है । इसमें 11 शहर शिमला, परवाणु, धर्मशाला, डमटाल (कांगड़ा), कालाअंब (सिरमौर), ऊना, सुंदरनगर (मंडी), बद्दी (सोलन), नालागढ (सोलन) और मनाली के आंकड़े जुटाए गए हैं। शिमला में दीवाली की रात को 90.3 रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आरएसपीएम) दर्ज किया गया । यह बीते दो साल के मुकाबले सबसे ज्यादा था । साल 2017 में शिमला में आरएसपीएम लेवल (ओल्ड बस स्टैंड) 78.9 था । साल 2018 में 76.0 था । लेकिन इस बार यह बढ़कर 90.3 आरएसपीएम तक पहुच गया है ।

हिमाचल में बढ़ रही है ठंड, पारा लुढ़कने से जमने लगी झीलें

द रीव टाइम्स

प्रदेशभर में दिनभर बादल छाए रहे । कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। सुबह और शाम की ठंड लगातार बढ़ रही है। शिमला से ठंडा सोलन हो गया है। सोलन में न्यूनतम तापमान 10.0, जबकि शिमला में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने शुरु में प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। जबकि बाद में प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री तक की गिरावट आई है। कल्पा में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। केलंग में सबसे कम तापमान 2.0, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

द रीव टाइम्स

जनजातीय जिला के विलिंग में चल रहा पैराग्लाइडिंग का ट्रायल, साहसिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा, युवाओं को मिलेगा रोजगार

साहसिक खेलों को बढ़ावा देने में जुटा पर्यटन विभाग लाहुल-स्पीति में भी साहसिक खेलों के माध्यम से यहां के पर्यटन करोबार को नई उड़ान देना चाहता है। इसी फेहरिस्त में इन दिनों लाहुल के विलिंग में जहां पैराग्लाइडिंग का ट्रायल चल रहा है, वहीं विभाग की टीम जिला के उन सभी स्थलों का दौरा भी कर रही है, जहां पैराग्लाइडिंग संभव हो सकती है। लंबे समय से लाहुल-स्पीति के पर्यटन कारोबार से जुड़े युवा जहां सरकार से यह मांग कर रहे थे कि लाहुल-स्पीति में भी सैलानियों के लिए साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं को तलाशा जाए, ताकि यहां पर पर्यटन कारोबार को और रफ्तार मिल सके। इस फेहरिस्त में इन दिनों लाहुल के विलिंग गांव में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल चल रहा है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर यह सफल होता है, तो आने वाले समय में सैलानियों को लाहुल में भी उड़ान भरने का मौका मिलेगा।

भीमाकाली मंदिर सराहन दूधिया रोशनी से नहाएगा अब रात को भी दिन की तरह दिखेगा भव्य नजारा

द रीव टाइम्स

एक बार फिर उत्तर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीमाकाली मंदिर सराहन दुधिया रोशनी से नहाएगा। मां भीमाकाली मंदिर परिसर में करीब पांच लाख रुपये से एलईडी लाइट लगाई गई है। इस लाइट के लगने से अब भीमाकाली मंदिर रात को भी दिन की तरह दिखेगा। मंदिर न्यास ने हाल ही में एलईडी लाइट लगाने का कार्य पूरा किया है। काफी समय से ये लाइट खराब चल रही थी। 120 फुट की ऊंचाई वाली इस लाइट को ठीक करने वाला न मिलने के कारण ये लाइट पुनः नहीं लग पा रही थी। भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट द्वारा काफी खोजबीन के बाद दिल्ली से इस कार्य मे माहिर लोगों को लाया गया। जिसके बाद इस लाइट को पुनः लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद इस लाइट को लगाने का काम पूरा किया गया। ये काम काफी जोखिम भरा होने के कारण ट्रस्ट प्रबंधन की सांसे तब तक थमी हुई थी जब तक इस लाइट को फिक्स कर इस काम मे जुटे व्यक्ति नीचे नहीं उतर गए। गौर हो कि सर्वप्रथम वर्ष 1998 में मां भीमाकाली मंदिर परिसर में करीब सात लाख रुपये की लागत से फ्लड लाइट स्थापित की गई थी। ऊपरी हिमाचल में इतनी ऊंची यह पहली लाइट लगी है। बीते मई माह में यह लाइट क्षतिग्रस्त हो गई थीए जिसके बाद यहां अंधेरा पसर गया था। इसके बाद भीमाकाली मंदिर न्यास ने लाइट को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया, लेकिन 120 फुट ऊंची इस लाइट को स्थापित करने के लिए अंबाला तक संपर्क किया गया, लेकिन कोई कारीगर नहीं मिल पाया। अंत में न्यास को दिल्ली स्थित टोरमेक कंपनी से एलईडी लाईट लगाने का मसला उठाया। दिल्ली की इस कंपनी के मजदूरों ने करीब पांच लाख रुपए की लागत से एलईडी लाइट लगाने का कार्य करीब दस दिन में पूरा किया। इस लाईट में कुल आठ बल्व लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में एक बार फिर दुधिया रोशनी लगने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने मंदिर न्यास की सराहना की है। वहीं मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन ने कहा है कि अब इन लाइटों की विशेष देखरेख होगी। ताकि फिर से ये लाइटें खराब न हो।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अस्पतालों के लिए 22.11 लाख का बजट स्वीकृत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

रोगी कल्याण समिति थानाकलां और बंगाणा की बैठक बंगाणा विश्राम गृह में एसडीएम बंगाणा विशाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 2018–19 का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए बजट पेश किया गया। बजट में अस्पतालों में गीजर, कुर्सियां-मेज, अलमारियां, स्टील बैंच के लिए आठ लाख 42 हजार रुपये की कार्य योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां और सिविल अस्पताल बंगाणा के लिए तेरह लाख रुपये की राशि 69 हजार रुपये शौचालयों की मरम्मत, प्रयोगशाला, वार्ड के लिए उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर और दवाइयों के प्रावधान के लिए राशि स्वीकृत हुई। इस मौके पर बीएमओ थानाकलां एनके आंगरा, जिला परिषद इंदु बाला, खंड विकासाधिकारी सोनू गोयल, सीडीपीओ हरीश मिश्रा, टीडब्ल्यू चमनलाल शर्मा, एसडीओ आईपीएच हरभजन सिंह, डॉ. अशोक दड़ोच, डॉ . अतुल राणा, अश्विनी कुमार, सुरेश परदेसी, तिलकराज, अच्छर सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रह

बल्ह में 63 बच्चों के लिए एक, जगरोट में तीन बच्चों के लिए 3 शिक्षक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

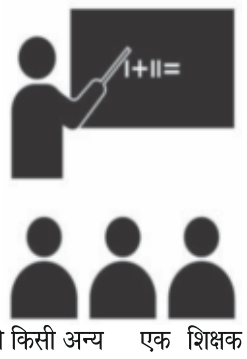

शिक्षा खंड बंगाणा के प्राथमिक स्कूल बल्ह में 63 छात्रों का भविष्य विभाग और सरकार की लाचारी की भेंट चढ़ रहा है। स्कूल में एक वर्ष से मात्र एक ही शिक्षक पांच कक्षाओं के 63 छात्रों को पढ़ा रहा है। पाठशाला में जलवाहक भी नहीं है। यहां पर नियुक्त जलवाहक को किसी अन्य पाठशाला में दो माह से डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार और विभाग लापरवाही कर रहे हैं। बल्ह पंचायत के लोग एक साल से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर पर भी कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। दुखी होकर अब अभिभावकों और एसएमसी कमेटी ने पाठशाला के गेट पर ताले लगाने की धमकी दी है। लोगों का आरोप है कि विभाग की नाकामी से 63 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है। उधर जगरोट पाठशाला में 3 बच्चों को तीन शिक्षक हैं। प्रदेश सरकार का नियम है कि 40 से अधिक बच्चों के लिए दो शिक्षकों की तैनाती आवश्यक है। यही नहीं जिले की 20 अन्य पाठशालाएं भी एक-एक शिक्षक द्वारा ही चलाई जा रही हैं।

एजेंसी में छापा, प्रतिबंधित दवाइयां बरामद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

पुलिस की एसआईयू टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंब में एक मेडिकल एजेंसी से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की खेप बरामद की है।

विभाग की छापामारी से नशा माफिया में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कई दवा विक्रेता अपनी दुकानें बंद करके इधर-उधर खिसक लिए। वहीं पुलिस की एसआईयू टीम ने मेडिकल एजेंसी से मिली प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अंब में ऊना रोड पर एक मेडिकल एजेंसी से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की 350 गोलियां बरामद की गई हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर विकास ठाकुर की अगुवाई में आईओ एसआईयू के हेड कांस्टेबल विकास दीप, कांस्टेबल राजन ठाकुर और सुच्चा सिंह की टीम ने अंब में ऊना रोड स्थित एक मेडिकल एजेंसी में छापामारी की। इस दौरान प्रतिबंधित दवाइयों की साढ़े तीन सौ गोलियां बरामद कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ड्रग इंस्पेक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि मेडिकल एजेंसी से प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मामले में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर विकास ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि जिला में अगर कहीं प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का कारोबार चल रहा है तो इसकी सूचना विभाग एवं पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

किराया न देने पर ठेकेदार को नोटिस, सलोगड़ा कूड़ा संयंत्र ठप

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

कूड़ा संयंत्र सलोगड़ा में कूड़े को नष्ट करने का काम ठप हो गया है। यहां टनों के हिसाब से कूड़ा एकत्र हो गया है। कूड़ा संयंत्र संचालक ने पिछले सात माह से नप को किराया नहीं चुकाया है।

इस पर नप ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि इस ठेकेदार ने यह काम किसी और को सबलेट कर रखा है। नोटिस के बाद कूड़ा संयंत्र में काम ठप हो गया है। इससे नप की मुश्किल बढ़ने वाली है। घरों से नियमित उठाए जा रहे कूड़े को ठिकाने लगाने का संकट नगर परिषद के सामने गहराता जा रहा है। नगर परिषद कर्मचारी शहर से रोजाना टनों के हिसाब से कूड़ा उठा रहे हैं और उसे सलोगड़ा में फेंका जा रहा है।

लेकिन इस कूड़े को नष्ट करने की प्रक्रिया ठप है। सलोगड़ा में कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए सलोगड़ा में संयंत्र स्थापित किया गया है। नगर परिषद ने इसके लिए एक ठेकेदार के साथ 40 हजार रुपये में एग्रीमेंट किया है।

कुछ माह तक कूड़ा संयंत्र चलाने के बाद संबंधित ठेकेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को तय किराये से अधिक पर कूड़ा संयंत्र सबलेट कर दिया। जिस ठेकेदार को कूड़ा संयंत्र सबलेट किया गया था।

उसने पिछले करीब सात माह से नगर परिषद का किराया नहीं चुकाया। जिसका भुगतान अब दो लाख 80 हजार रुपये बन चुका है। इसके अलावा इस भुगतान पर नगर परिषद ने कुछ टैक्स भी लगा रखे हैं।

लिटफेस्ट के आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

कसौली में बीते दिनो आयोजित खुशवंत सिंह लिटफेस्ट पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कसौली क्लब में आयोजित लिटफेस्ट कार्यक्रम में पहुंची लेखिका एवं साहित्यकार तवलीन सिंह, लेखक राधा कुमार, साहित्यकार सादिया देहलवी और उनके साथ आए वक्ताओं व आयोजक राहुल सिंह के खिलाफ बजरंग दल ने कसौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बजरंग दल ने कहा है कि आयोजक और लिटफेस्ट में आए वक्ताओं ने देश और केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है।

इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 11 से 13 अक्तूबर तक चले लिटफेस्ट में साहित्यकार तवलीन सिंह ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार इसे पुनः बहाल करे। लेखक राधा कुमार ने कहा कि कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं।

उन्हें भारत सरकार की तरफ से थोपे जा रहे आदेश स्वीकार्य नहीं हैं। बजरंग दल के प्रांत सहसंयोजक पवन समेला, जिला सहसंयोजक संजीव कुमार और मुकेश काश्ता ने शिकायत में कहा कि साहित्यकार सादिया देहलवी ने भी लिटफेस्ट मंच से कहा कि खुशवंत सिंह को पाकिस्तान से लगाव था, वह मुस्लिम धर्म के करीब थे और बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे। कसौली थाना

प्रभारी लायक राम ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। लिटफेस्ट के आयोजनकर्ता खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता लोकतंत्र के विरोधी हैं। वे किसी मसले पर चर्चा नहीं चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के पैनल में भाजपा प्रवक्ता भी थे, तो क्या उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।

कंडा गांव की खस्ताहाल सड़क से ग्रामीण परेशान, हादसे का अंदेशा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

विकास खंड धर्मपुर के तहत हुडंग ग्राम पंचायत के गांव कंडा में सड़क की दयनीय स्थिति बड़े हादसे के इंतजार में है। आलम यह है कि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा घट सकता है लेकिन लोक निर्माण विभाग अभी भी मूकदर्शक बना है। विभाग ने सुखी जोहड़ी सड़क धंसने के बाद सबक नहीं लिया है। विभाग यदि समय रहते कदम उठा लेता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बहरहाल, कंडा में भी सड़क की दयनीय स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा भी लिया है लेकिन अभी तक इस कार्य को शुरू नहीं किया है। अधिक बरसात से जहां प्रदेश की अधिकतर सड़कों को नुकसान हुआ है, वहीं कंडा की यह सड़क भी अछूती नहीं रही है। यह सड़क धर्मपुर - कुनिहार - कसौली - बद्दी को जोड़ती है तथा अधिकांश भारी वाहनों की आवाजाही इसी सड़क से होकर है। ऐसे में इस स्थान पर दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने स्थानीय मंत्री व विभाग से आग्रह किया है कि टूटी हुई सड़क पर जल्द पक्का डंगा लगाया जाए। स्थानीय लोगों पवन पंवर, रीना, पुष्पा, नरेश, विक्की, मोहन, दीपक,

लता, लीला देवी, रमा, मनोज, कमल, आज्ञा दत्त का कहना है कि कंडा रोड की हालत खस्ता होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर, अधिशासी अभियंता कसौली राजेश गर्ग ने कहा मामला उनके ध्यान में है। जल्द ही डंगे का एस्टिमेट बनाकर टेंडर लगाया जाएगा।

पच्छाद में भाजपा की हैट्रिक, निर्दलीय उम्मीदवार दयाल प्यारी का शानदार प्रदर्शन

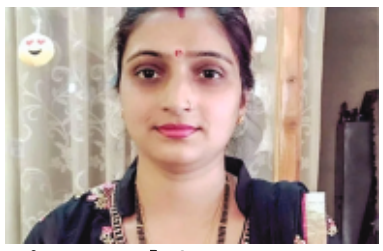

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर यहां हैट्रिक बनाई है। वहीं, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से पहली महिला विधायक बनने का रिकॉर्ड भी रीना कश्यप के नाम जुड़ गया है। रीना कश्यप ने कांग्रेस के गंगू राम मुसाफिर को कड़े मुकाबले में 2808 मतों के अंतर से हरा दिया। जबकि भाजपा से बागी होकर मैदान में उतरी दयाल प्यारी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। भले ही वह तीसरे स्थान पर रहीं। लेकिन, भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर 11698 मत हासिल करने में सफलता हासिल की। रीना को 40.85 फीसदी वोट पड़े।

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में इस बार तीन प्रत्याशी होने से मुकाबला रोचक रहा। मतगणना केंद्र में अमूमन दो-तीन राउंड के बाद हार-जीत के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और केंद्र के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक नारेबाजी करते हुए जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन, पच्छाद विस क्षेत्र में इस बार ऐसा नहीं हुआ। बेहद करीबी मुकाबले में भाजपा की रीना कश्यप ने कांग्रेस के जीआर मुसाफिर को हराकर भाजपा की हैट्रिक बनाई।

इससे पहले भाजपा के ही सुरेश कश्यप इस सीट से लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव में भाजपा की रीना कश्यप को 22167, कांग्रेस के जीआर मुसाफिर को 19359, आजाद उम्मीदवार दयाल प्यारी को 11698, आजाद उम्मीदवार सुरेंद्र पाल को 292, आजाद उम्मीदवार पवन कुमार को 428 मिले। जबकि 318 ले नोटा दबाया और 47 वोट रद्द हुए।

अतिक्रमण हटाने पर बवाल, नप टीम से भिड़ गए कारोबारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सोलन शहर में अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल हुआ। नप की टीम और कारोबारियों में बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दुकान के कर्मचारी ने जबरदस्ती सामान जीप से उतार लिया। पुलिस इसे जीप में डालकर थाने ले गई। नप को शिकायतें मिल रही थी कि बाजार में कारोबारी अतिक्रमण कर रहे हैं। इस पर नप की टीम वाहन के साथ अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची और सामान को उठाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दुकान के आगे रखे सामान को हटाकर जीप में डाला गया। इस पर कारोबारी भड़क गए और टीम के साथ बवाल हो गया। अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ी मुहिम का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। इस बीच एक सेल्समैन उग्र हो गया और उसने जीप पर लादे गए सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पूछताछ पूरी होते ही पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मंगलवार को भी नगर परिषद ने शहर के बाजारों से अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई की। जिसमें किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं गया। कार्रवाई की भनक लगते ही कारोबारियों में हड़कंप मच गया। लेकिन कारोबारियों को सामान को समेटने का मौका तक नहीं मिला। जिसके चलते अप्पर बाजार में सरेआम सड़क के बीच में अतिक्रमण कर बैठे कारोबारियों पर शिकंजा कसकर गाड़ी में सामान को भर लिया। इससे पूर्व भी नगर परिषद की ओर से कारोबारियों को सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन कारोबारियों ने दिए गए निर्देशों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस किए जा रहे अतिक्रमण से जहां लोगों को परेशानियों को सामना आए दिन करना पड़ रहा है।

फलदार पौधों की रोपाई के लिए बगीचे तैयार करें किसान–बागवान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सर्दी के मौसम में किसान-बागवान विभिन्न फलदार पौधों की रोपाई का कार्य शुरू कर देते हैं। इसके लिए बागवानों को बारिश का इंतजार होता है। इस बार समय पर अच्छी बारिश हुई है। अब बागवान सेब, खुमानी, प्लम, नाशपाती और अखरोट की रोपाई के लिए गड्ढे बनाने का कार्य शुरू कर सकते हैं। नए बगीचे लगाने से पूर्व और बगीचों की तुड़ाई के बाद मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजें। नौणी विवि के विशेषज्ञों ने किसानों-बागवानों को सलाह दी है कि वर्षा से खेतों में अच्छी नमी है, जिसमें वे अब अपने खेतों और बगीचों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें विभिन्न फलदार पौधों की रोपाई के लिए करीब तीन फुट गड्ढा खोदें और उसमें गोबर मिलाएं। नौणी विवि के विभागाध्यक्ष डा. सतीश भारद्वाज के मुताबिक बगीचे में गिरे फल-पत्तियों को एकत्रित कर गोबर के गड्ढों में डालकर उन्हें नष्ट करें। इससे दिसंबर और जनवरी से पौधों की रोपाई का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की तुड़ाई का काम जारी रखें। अखरोट, पीकन नट, किवी, मौसमी तथा माल्टा की तुड़ाई आरंभ कर दें।

पशुधन संबंधित कार्य

इस माह दिन-रात के तापमान में अंतर होने के कारण पशुओं में श्वास की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। पशुपालकों को रात के समय में पशुओं नवजात बछड़ों को कम तापमान से बचाव की सलाह दी है। नवजात और युवा पशुओं को रात के समय सूखी बोरियों से ढककर रखें। पशुओं के लिए बिछाए जाने वाले घास या भूस के बिछोने को प्रतिदिन बदल दें, जिससे गौशाला का फर्श साफ तथा सूखा रहे। पहाड़ों के कुछ क्षेत्रों में इस समय शहद का प्रवाह होता है तथा उसके अनुसार ही मौनवंशों का प्रबंध करें। मौनवंशों में सफाई का ध्यान रखें तथा तलपटों की विशेषरूप से सफाई करें।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

धर्मशाला में भाजपा को फिर मिली जीत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

लोकसभा चुनावों के बाद खाली हुई धर्मशाला विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनावों में भाजपा ने आसान जीत दर्ज की। 21 अक्तूबर को हुए उपचुनावों में धर्मशाला में भाजपा के विशाल नैहरिया 6758 मतों से जीते। जबकि आजाद प्रत्याशी राकेश कुमार को मिले 16740 वोट। यहां कुल 82137 मतदाता थे जिनमें से 52485 वोट डाले गए। 430 लोगों ने नोटा दबाया। 24 मत रिजेक्ट हुए। 24 अक्तूबर को चुनावों का परिणाम आते ही धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं।

धर्मशाला चुनाव परिणाम

- भाजपा प्रत्याशी - विशाल नैहरिया 23498
- आजाद प्रत्याशी - राकेश कुमार 16740
- कांग्रेस प्रत्याशी - विजय इंद्र करण 8212
- आजाद प्रत्याशी - निशा कटोच 435
- आजाद प्रत्याशी - पुनीश शर्मा 2345
- आजाद प्रत्याशी - डॉ. मनोहर लाल धीमान 887
- आजाद प्रत्याशी - सुभाष चंद शुक्ला 368

ऊना के बाद हिमाचल के तीन और जिलों में पेट्रोल-गैस की खोज

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

हिमाचल के चार जिलों में पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस की खोज की जा रही है। ऊना के बाद अब बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर जिलों में सर्वे हो रहा है। इन दिनों बिलासपुर के स्वारघाट व इससे सटे जिला सोलन के रामशहर क्षेत्र में 76 किलोमीटर की सीधी लाइन में दिन-रात काम किया जा रहा है। भू-वैज्ञानिक कई स्थानों पर 60 फीट तक गहरी बोरिंग करके केंद्र को डिजिटल आंकड़े भेज रहे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के माध्यम से अल्फा जीईओ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद कंपनी के वैज्ञानिक दिसंबर तक सर्वे को पूरा कर लेंगे। ओएनजीसी से सेवानिवृत्त भू-वैज्ञानिक एवं प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉ. डीआर कोठियाल ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल सरकार व संबंधित जिलों के प्रशासन के अधिकारियों का उन्हें बहुत सहयोग मिल रहा है जिससे कार्य दिन-रात प्रगति से चल रहा है। स्वारघाट के बेस कैंप में 24 घंटे वैज्ञानिकों की ओर से डिजिटल आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल में पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो भारत सरकार के साथ ही हिमाचल प्रांत को भी बड़ा फायदा होगा।

प्लास्टिक के भंडारण के लिए बनेगा भवन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

सुजानपुर नगर परिषद की बैठक अध्यक्ष अशोक मेहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी जरूरतमंद पात्र परिवार होगा, उसे बीपीएल परिवार में शामिल किया जाएगा। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 7 में एक कमरे का निर्माण किया जाएगा। जिसमें प्लास्टिक का भंडारण किया जाएगा। नगर परिषद के लोगों से प्लास्टिक 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि टैक्सी स्टैंड के स्थान को भी पक्का किया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही शहर में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, वार्ड

नंबर दो में मुख्य बाजार को जाने वाले रास्ते और न्हौण मार्ग को पक्का करवाने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। पोड़ियां मोहल्ला की सड़क को भी दुरुस्त किया जाएगा। बैठक में नगर परिषद के ईओ संजय कुमार, उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी, मनोज ठाकुर पार्षद सुमन अटवाल, ज्योति शर्मा, रेणु गुप्ता मनोज नाग आदि मौजूद रहे।

घुग्घर के बारह साल के बच्चे ने रोंगला चोटी पर फहराया तिरंगा

द रीव टाइम्स, कांगड़ा

धौलाधार पर्वत की चोटी रोंगला को एक बारह साल के छात्र ने ही फतह कर लिया है। कठिन पहाड़ियों और दुर्गम रास्ते से होते हुए इस लड़के ने समुद्र दल से करीब 15 हजार फीट ऊंची चोटी को फतह किया है। इस चोटी को फतह करने में टीम को तीन दिन का समय लगा है। इस उम्र में छात्र ने चोटी के टॉप पर पहुंचकर भारत का तिरंगा भी फहराया है। घुग्घर के रहने वाले बारह साल के अरमान कलहान ने अपनी टीम के साथ बंदला के धौलाधार की चोटी रोंगला को फतह कर दिया है। यह चोटी वीरनी माता मंदिर के ऊपर सीधे खड़ी है। अरमान सेंट पॉल स्कूल पालमपुर में आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। अरमान का कहना है कि उसने यह चढ़ाई अपनी टीम के साथ तीन दिन तक पूरी की। अरमान के साथ उसके पिता अनिल कलहान, देव, सुभाष चंद और मास्टर साहिल सिंह मौजूद रहे। अरमान के पिता अनिल कलहान का कहना है कि उनके बेटे को शुरू से ही साहसिक गतिविधियों का शौक है।

हमीरपुर की 33 पंचायतों को मिलेंगे नए मुखिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने पंचायती राज उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिले में होने वाले उपचुनावों में 2 प्रधान, 5 उपप्रधान तथा 26 पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। उपचुनाव के चलते 21 अक्तूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव के लिए 1, 2 और 4 नवंबर को प्रातः 11 बजे से शाम 3 तीन तक संबंधित पंचायतों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 नवंबर को होगी। 7 नवंबर को शाम 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक होंगे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना होगी। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने विकास खंडों में मतदान केंद्रों के नाम प्रकाशित करने के लिए खंड विकास अधिकारी हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन, बिझड़ी, बमसन और भोरंज को प्राधिकृत किया है। साथ ही बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर उन्हें उप-चुनाव के लिए आवश्यकता अनुसार सहायक रिर्टनिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया है।

दलाईलामा से मिले विभिन्न देशों के 26 युवा नेता

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के देशों के 26 युवा नेता यूनाइटेड नेशनस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस (यूएसआईपी) की अध्यक्ष नैंसी लिंडबोर्ग के नेतृत्व में मैकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में धर्मगुरु दलाईलामा से मिले। दुनिया के 26 युवा नेताओं ने दलाईलामा को शांति का प्रतीक बताया।

दल ने दलाईलामा के साथ विभाजित समाज में समावेशी शांति के बारे में वार्ता की। घंटे भर चली बातचीत में युवा नेताओं ने मानवता की एकता को अपनाने, आंतरिक मूल्यों के शिक्षण को एक अकादमिक विषय के रूप में पढ़ाने

और समग्र शिक्षा के माध्यम से गलत भावनाओं को बदलने पर विचार किया। धर्मगुरु दलाईलामा ने कहा कि हम सभी समान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं वाले मनुष्य हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य खुशी हासिल करना और समाज को दुखों से मुक्त करना है। उन्होंने दोहराया कि दया मानव की सबसे सहज प्रकृति है। उन्होंने सुझाव दिया कि आदर्श शिक्षा प्रणाली वह है जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ अहिंसा और करुणा दोनों का प्राचीन भारतीय ज्ञान है। हम कमोबेश भौतिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लेकिन विभिन्न धार्मिक परंपराओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कहा कि नफरत और आलोचनाओं से निपटने के लिए धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना होगा।

उच्चाधिकारियों की मंजूरी के बाद होगा फोरलेन निर्माण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

कीरतपुर - नेरचौक फोरलेन के बदले गए रूट पर अब कहां से निर्माण कार्य होगा इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगामी कार्रवाई होगी। अब विभाग के उच्च अधिकारी तय करेंगे की फोरलेन निर्माण बदले गए प्लान के तहत होगा या फिर तय रोड अलाइनमेंट प्लान के तहत। यह जानकारी वन अधिकारी बिलासपुर सरोज भाई पटेल ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 7439 दिनांक 17-10-2019 के तहत दी है। उल्लेखनीय है कि फोरलेन निर्माण के दौरान निर्माण कर रही कंपनी और एनएचएआई ने अपनी मर्जी से ही रोड अलाइनमेंट प्लान बदल दिया था जिसकी शिकायत फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार देहरादून को की थी। मंत्रालय ने जांच के लिए राज्य सरकार तथा राज्य सरकार ने मुख्य अरण्यपाल वन शिमला को जांच के आदेश दिए। इस पर जिला वन अधिकारी ने तीन विभागों की 15 सदस्यीय टीम बना कर जांच करवाई। जांच में विभागों ने पुष्टि की कि 10 किमी में करीब पांच किमी के रूट को बदला गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति ने मंत्रालय से जानकारी मांगी कि अब सड़क का निर्माण कहां होगा बदले हुए रूट पर या भारत सरकार की ओर से मंजूर रूट पर। इस पर जिला वन अधिकारी ने पहले यह जानकारी दी कि यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है लेकिन उसके बाद साथ में यह भी पुष्टि की है कि उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना कहीं भी काम नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस बदले हुए रूट पर उपरोक्त विभागों की मिली भगत और

अधिकारियों के निजी हित के लिए टनल नंबर दो सुनण, थापना, टाली, तुननु ब्रिज, टनल नंबर तीन, ढलयार, पट्टा, भराड़ी ब्रिज को बदल दिया गया। जबकि बाकि अन्य तहसीलों में बदले गए रूट की जांच चली हुई है। इसमें निरीक्षण टीम को अब भूमि अधिग्रहण प्लान व आरओडब्ल्यू को ओवर लैंप कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट डीसी बिलासपुर तथा फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को रिपोर्ट भेजनी तय है।

प्रदेश सरकार 345 विस्थापितों के घरों को तोड़ने से बचाने को उठाए कदम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार भाखड़ा विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के आकलन करने के लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी का तुरंत गठन किया जाए ताकि शीघ्र अतिशीघ्र यह कमेटी बिलासपुर में आकर उनकी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके और विस्थापितों को आवश्यक राहत मिल सके। परिधि गृह में भाखड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सात व आठ अक्तूबर को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यहां प्रथम बार पधारे जगत प्रकाश नड्डा को समिति के शिष्ट मंडल की ओर से दिए गए विस्तृत ज्ञापन का विवरण देते हुए कहा कि समिति ने उनसे भी उपरोक्त कमेटी का गठन प्राथमिकता से करवाने सहित नगर के 345 विस्थापितों के घरों को तोड़ने के आदेशों से बचाने का भी आग्रह किया है ताकि नगर के विस्थापित दोबारा उजड़ने से बचाए जा सकें।

समिति सरकार की ओर से हाल ही में उनके संदर्भ में घोषित अतिक्रमण नीति पर भारी निराशा व्यक्त की और मांग की कि पुरानी घोषित नीति की सभी शर्तों को वापस लिया जाए और समिति के सुझावों के अनुसार उनके अतिक्रमण नियमित किए जाने के आदेश दिए जाएं। कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन को नगर के साथ लुहणू से गुजारे जाने के समाचारों के कारण यदि लखनपुर से लेकर कोठी तक फ्लाई

ओवरों का निर्माण नहीं किया गया तो आधे शहर को उजाड़ा जाना निश्चित है। जबकि पूर्व की ओर मारकंड से मुख्य बाजार को टनल निकाल कर नगर के मुख्य बाजार में से गुजरते हुए बस्सी, मारकंड, बिलासपुर, बेरी दड़ोला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण करने की सरकार द्वारा घोषित योजना से भाखड़ा विस्थापित पहले ही बुरी तरह से चिंतित और दुखी हैं क्योंकि यदि ऐसा होता है तब भी आधे शहर को उजड़ना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री आदर्श योजना में शामिल हुआ कठियाणवीं गांव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

भोरंज उपमंडल के कड़ोहता पंचायत के कठियाणवीं गांव को सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श गांव योजना में शामिल किया है। इसे लेकर प्रशासन ने कठियाणवीं गांव में बैठक का आयोजन किया।

इसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने गांव में होने वाले विकास कार्यों से ग्रामीणों को अवगत करवाया।

इस दौरान कड़ोहता पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी का कठियाणवीं गांव को आदर्श गांव योजना में डालने और विकास में पिछड़े गांव को विकसित करने में सहयोग देने का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में कड़ोहता पंचायत के गांव जाड़, अंबीं, गाहरी, झलेहड़ा के ग्रामीण काफी संख्या में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने गांव की बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं को विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष उठाया।

इस दौरान पंचायत प्रधान संतोष धीमान, उप प्रधान विरेंद्र डोगरा, सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी प्रकाश चंद, दिले राम, कश्मीर सिंह, मेहर सिंह, जीवन, पुरशोत्तम, जगदीश चंद,

परजा राम, सन्नी, विनोद कुमार, बहबी, संजू, रानी विक्की, अनीता देवी, वीना देवी, कांता देवी, चंद्रा, आशा देवी, बिमला देवी, राजो देवी, कमला देवी, ज्योति, प्रियंका, रीना, मीरा देवी, सुंदरी देवी तथा रक्षा देवी और अन्य उपस्थित रहे।

जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र हुए ऑनलाइन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा अब हर दिन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए बाल विकास विभाग ने पोषण योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता को स्मार्ट मोबाइल फोन आवंटित किए हैं। इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महीने भर की रिपोर्ट एक साथ विभागीय अधिकारी को सौंपती थीं लेकिन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को हर दिन विभाग के अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी।

समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से पोषण योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की हाजिरी, बच्चों को हर दिन क्या खिलाया गया और किस प्रकार से उन्हें प्राथमिक स्तर की चीजें सिखाई जा रही हैं।

इस सबका ब्योरा ऑनलाइन रहकर विभाग के अधिकारियों को देना होगा। विभाग के आला अधिकारी हर दिन आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन निरीक्षण करेंगे ताकि सरकार की ओर से बच्चों को दी जाने वाली हर सुविधा का आंकलन किया जा सके।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

फ्लाइंग प्रतियोगिता में जीवासा देश में द्वितीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

राजस्थान के जोधपुर में हुए अखिल भारतीय वायुसैनिक कैंप में कुल्लू की कैडेट जिवासा ठाकुर ने फ्लाइंग प्रतियोगिता में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिवासा देशभर के 592 कैडेटों के बीच हुई प्रतियोगिता में द्वितीय रहीं। अखिल भारतीय वायुसैनिक कैंप में एचपी वन एयर स्क्वाड्रन के चार कैडेट जिवासा ठाकुर, हिमांशु, विकास गुलेरिया, कैडेट कोर्पोरल विनय ठाकुर ने हिस्सा लिया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। इस दौरान फ्लाइंड कंपीटिशन में जिवासा ठाकुर का शानदार प्रदर्शन रहा। जिवासा को एनएसीसी के डायरेक्टर जनरल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कुल्लू जिले की कैडेट की उपलब्धि से एनसीसी एयरविंग में खुशी का माहौल है। कैडेट जीवासा बॉटनी की द्वितिय वर्ष की छात्रा हैं। वह अपनी कक्षा की टॉपर भी हैं। एचपी वन एयर स्क्वाड्रन के कमान अधिकारी विंग कमांडर अनिल तिवारी ने कहा कि यह कुल्लू जिले के साथ हिमाचल के लिए भी उपलब्धि है।

करसोग में 27 फर्जी बीपीएल परिवार सूची से बाहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

करसोग में बीपीएल सूची में शामिल हुए अपात्र लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। मैंडी पंचायत में एसडीएम की जांच के बाद फर्जी तरीके से गरीब बने 27 सुविधा संपन्न परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने के आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित पंचायत सचिव को अगली ग्राम सभा की बैठक में इन परिवारों को बाहर कर इतने ही पात्र लोगों को सूची में शामिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले पांगणा पंचायत में भी एसडीएम की जांच के बाद 22 परिवारों को बीपीएल सूची से हटाया जा चुका है। जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम की इस तरह की बड़ी कार्रवाई से पात्र लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि करसोग की पांच पंचायतों से बीपीएल सूची में फर्जी तरीके से लोगों को शामिल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस पर पांच पंचायतों को 15 दिन में एसडीएम कोर्ट में दस्तावेज जमा करने के आदेश जारी किए गए थे।

विकास खंड करसोग की 5 पंचायतों से एसडीएम को बीपीएल सूची में अपात्र लोगों को शामिल करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। एसडीएम करसोग सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि मैंडी पंचायत से बीपीएल सूची से संबंधित शिकायत मिली थी। यहां से ऐसे 29 लोगों की सूची दी गई थी। जब जांच की गई तो 27 लोगों को पात्र न होने के कारण सूची से बाहर करने के आदेश किए।

कायाकल्प टीम ने किया चंबा का दौरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

मेडिकल कालेज चंबा के अस्पताल का हाल ही में कायाकल्प की तीन सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अस्पताल में वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कायाकल्प की टीम रसोईघर से लेकर सभी वार्डों में पहुंची। इस निरीक्षण के दौरान टीम के संग चंबा अस्पताल के चिकित्सक भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण की टीम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। जानकारी के अनुसार कायाकल्प टीम द्वारा अस्पताल की इंडोर व्यवस्था में कुछ खामिया भी पाई गई है। इस दौरान टीम ने व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रबंधन को दिशा-निर्देश भी दिए है। साथ ही आउटडोर की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए। टीम ने अस्पताल प्रबंधन को बायो मेडिकल बेस्ट की व्यवस्था को भी सुधारने को कहा है। बताते चलें कि इसी तरह की अन्य टीम प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है। इसमें सभी टीमों द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर जिला अस्पताल का चयन होगा। इसमें प्रथम रहने वाले अस्पताल को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस धनराशि से अस्पताल प्रबंधन अस्पताल में विकास के कार्य करवा सकते हैं। उधर, मेडिकल कालेज चंबा के चिकित्सा अधीक्षक डा. विनोद शर्मा ने बताया कि कायाकल्प की टीम ने अस्पताल का दौरा किया है। टीम द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर पाया गया है। साथ ही टीम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार की है।

चंबा के भडल की मक्की देश में सर्वश्रेष्ठ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने जिला चंबा के किसानों की मक्की के बीज को लेकर तकदीर बदल दी है। चंबा की पंचायत भडल में बीजी जाने वाली मक्की की गुणवत्ता पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पाई गई है। बीज में बेहतरीन प्रोटीन और शर्करा है। दिल्ली में तीन किस्मों के मक्की बीज का पंजीकरण किया गया। इससे आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिकी सुधर सकती है। मक्की की गुणवता को देख कृषि विवि के कुलपति प्रो. अशोक सरियाल और चंबा की भड्ल पंचायत के किसानों को नेशनल प्लांट जीनोम सेवियर कम्यूनिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही किसानों को दस लाख रुपये नकद, ट्राफी और प्रमाण पत्र दिया गया।

यह सम्मान केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में दिया। कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भडल क्षेत्र की हाच्छी (सफेद), रैट्टी (लाल) व चिटकुरी (पॉप कॉरन) मक्की की तीन स्थानीय किस्मों का संचयन, मूल्यांकन व चिह्नितकरण किया।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए आवेदन 30 नवंबर तक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जल संरक्षण में सराहनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, शिक्षण संस्थानों, अन्य संस्थानों या संस्थाओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस वर्ष भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इन पुरस्कारों के लिए 30 नवंबर तक अहनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अक्षय सूद ने बताया कि ये आवेदन ऑनलाइन प्लेटफार्म माई जीओवी डॉट इन पर किए जा सकते हैं। ये आवेदन ईमेल से टीएसएमएसएमएल - सीजीडब्ल्यूबी एट द रेट एनआईसी डॉट इन पर भी भेजे जा सकते हैं। एडीएम ने पात्र संस्थानों या संस्थाओं से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अपील की है।

कामकाजी माताओं के बच्चों लिए क्रेच खोलने की योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के समन्वय से क्रेच खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रेच खोलने के लिए सबसे पहले स्थान चिन्हित किए जाएंगें। मॉडल आधार पर पहला क्रेच उपमंडल चंबा में खोलने की योजना है। इनमें केयरटेकर नियुक्त कर बच्चों की सुरक्षा व प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं संवीक्षा समिति की बैठक में विवेक भाटिया ने गांव में मातृ शिशु बैठक में पोषण के बारे में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों तथा बौने बच्चों को संदर्भ सेवाएं प्रदान करने में और दक्षता से कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास सेवाए कार्यक्रम के अंर्तगत वर्तमान में जिला में संचालित 1495 आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा स्कूल छोड चुकी 11 से 14 साल की किशोरियों को पूरक पोशाहार से लाभांवित किया जा रहा है।

चंबा में पंचायत उपचुनावों में 17 पदों पर चुने जाएंगे पंचायत प्रतिनिधि

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

प्रदेश में पंचायतीराज उपचुनाव के शंखनाद के साथ ही जिला पंचायत कार्यालय ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर कदमताल शुरू कर दी है। पंचायतीराज कार्यालय से जारी सूची के अनुसार विभिन्न पंचायतों में 17 प्रतिनिधियों के पदों पर उपचुनाव होंगे। यह पद विभिन्न कारणों से रिक्त चले हुए हैं। उप चुनावों की घोषणा के बाद पंचायतीराज विभाग ने विभिन्न ब्लॉकों में भरे जाने वाले पदों की सूचना आरक्षण सहित जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पद्दर साहो के वार्ड पद्दर में एससी, द्रम्मण पंचायत के वार्ड नंबर ओबड़ी में सामान्य, रूपणी पंचायत के वार्डर नंबर दो घाड़ी में सामान्य, पलूंई पंचायत में पंचायत समिति सदस्य का पद एसटी श्रेणी के तहत भरा जाएगा। इसके अलावा विकास खंड मैहला में उटीप पंचायत प्रधान महिला एससी वर्ग के लिए आरक्षित है।

विकास खंड तीसा की देहरा पंचायत में वार्ड सदस्य मौड़ा-5 का पद महिला के लिए आरक्षित है। जसौरगढ़ के वार्ड उथपुर में जनरल, भराड़ा पंचायत के भराड़ा-1 में जनरल श्रेणी से वार्ड सदस्य का पद भरा जाएगा। विकास खंड सलूणी की पंचायत दिघाई में वार्ड प्रजना-2, ग्राम पंचायत सियुला के वार्ड धनवल महिला के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जिले के सबसे बड़े विकास खंड भटियात में सात पद उपचुनाव के जरिये भरे जाएंगे। इसमें जियुंता कथला और रूल्याणी पंचायत में उपप्रधान का पद भरा जाएगा। जबकि जियुंता पंचायत के वार्ड नंबर पांच में सामान्य श्रेणी से वार्ड सदस्य, मनोला पंचायत के गरंगड़ में महिला के लिए आरक्षित वार्ड सदस्य, समलेऊ पंचायत के द्रबड़ में एससी श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित, कथेट पंचायत के वार्ड छत्तरेल में वार्ड सदस्य का पद सामान्य श्रेणी और खनोड़ा पंचायत का खनोड़ा-4 सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला पंचायत अधिकारी हरबंस लाल ने बताया कि पंचायत उपचुनावों में जिले के विभिन्न विकास खंडों में 17 पंचायत प्रतिनिधियों के पद भरे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

औषधीय खेती के लिए सरकार देगी सब्सिडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास दो हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है। किसान संयुक्त रूप से भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

5 किलीमीटर के दायरे में रहने वाले तीन गांव के किसान एक समूह या क्लस्टर बनाकर औषधीय खेती के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रैहन रखी हुई भूमि पर भी औषधीय खेती की जा सकती है।

चयनित 7 औषधीय पौधों अतीस, कुटकी, कुठ, सुगंधबाला, अश्वगंधा, सर्पगंधा तथा तुलसी की खेती को वित्तीय सहायता दी जा रही है। औषधीय एवं जड़ी-बूटियों की खेती शुरू करने के लिए किसान को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को आवेदन करना होगा।

आवेदन पत्र में वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिए खेती को उपलब्ध भूमि, किस प्रजाति की औषधीय खेती की जानी है, क्लस्टर में शामिल होने वाले प्रत्येक किसान की भूमि की स्थिति खसरा नंबर होना चाहिए। क्लस्टर में शामिल किसानों का संयुक्त आवेदन, स्टांप पेपर पर यह हल्फनामा देना होगा कि सरकार या अन्य किसी एजेंसी से कोई अनुदान नहीं लिया है। आवेदन पत्रों के उचित सत्यापन के बाद मामला स्वीकृति के लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड को भेजा जाएगा।

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत, जोगिंद्रनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन ने बताया कि सरकार राज्य औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। किसानों से व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर अनुकूल जलवायु के तहत औषधीय खेती अपनाने का आह्वान किया है।

कूड़ा संयंत्र के लिए अब सख्ती से जगह लेगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

शहर में लगने वाले कूड़े संयंत्र का हर जगह विरोध हो रहा है। ऐसे में अब सरकार कूड़ा संयंत्र के लिए सख्ती से जगह लेगी। जगह चिह्नित होने के बाद अब कुल्लू में कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें लोगों के विरोध के आगे प्रशासन व सरकार घुटने नहीं टेकेगा।

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में कहा कि अच्छे काम के लिए लोगों को विरोध सहन नहीं किया जाएगा। बार-बार लोगों के हो रहे विरोध के बाद अब सख्त होने की आवश्यकता है। इसलिए अब सरकार कूड़ा संयंत्र को भूमि दिलाने के लिए सख्त बरतेगी। वन, परिवहन, युवा सेवाएं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों ने जैसे कूड़ा संयंत्र को जमीन न देने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि पीज में एक जगह चिह्नित की गई तो महाराजा क्षेत्र के लोग विरोध में आ गए। सारे शहर का कूड़ा यहां पर डालने नहीं देंगे। दुर्गानगर में एक जगह फाइनल हुई तो सारी कोठी के लोगों ने इस पर विरोध जताया। इसके साथ भुंतर की तरफ एक भूमि चयनित हुई तो 50-60 बुद्धिजीवियों ने आकर विरोध किया। अगर ऐसे ही विरोध होता रहा तो कूड़ा संयंत्र नहीं लग सकेगा।

अगर इसमें आवश्यकता पड़ती है तो इसमें सख्ती भी की जाएगी। गौर रहे कि नगर परिषद कुल्लू को कूड़ा संयंत्र के लिए भूमि न मिलना गले की फांस बना हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद निश्चित तौर पर नगर परिषद की मुश्किलें कम होंगी।

दस करोड़ की लागत से बनेगी बंदरोल सब्जी मंडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

देवभूमि कुल्लू के बंदरोल और पतलीकूहल में जल्द ही वर्ल्ड बैंक की मदद से सब्जी मंडियों के लिए भवनों का निर्माण होगा। अभी तक टेंटों में चल रही इन मंडियों में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला चकाचक भवनों को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंदरोल सब्जी मंडी के लिए तो एस्टिमेट तैयार हो गया है। इसके नक्शे के अलावा ब्लू प्रिंट भी बना दिया गया है। बंदरोल में बनने वाली सब्जी मंडी के लिए दस करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। वहीं, पतलीकूहल में नई सब्जी मंडी भवन और नीलामी मंच के निर्माण को एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। बड़ाग्रां पुल के समीप पतलीकूहल की पुरानी सब्जी मंडी के फोरलेन की जद में आ जाने के चलते इसे जटेहड़ बिहाल में शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन, अपना भवन न होने के चलते इस मंडी को भी टेंटों से ही कारोबार चलाना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि जल्द ही इस भूमि का कायाकल्प कर यहां सब्जी मंडी में नया भवन बनने जा रहा है। दोनों मंडियों में हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन, बंदरोल और पतलीकूहल सब्जी मंडियों में नीलामी मंच और भवन न होने के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात में मंडियों में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। जिससे आढ़तियों के अलावा बाहर से आए सेब कारोबारियों और बागवानों के भारी दिक्कत होती है। मंडियों के अंदर माल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। एपीएमसी के सचिव सुशील गुलेरिया ने बताया कि जल्द ही मंडियों में भवन तैयार होंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जानिए बच्चों के कौन -कौन से अधिकार हैं

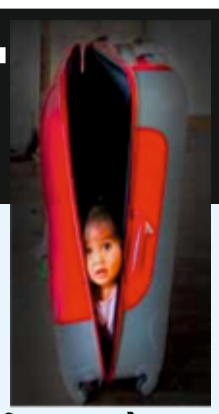

बच्चों के अधिकारों के बारे में लोग कम ही बात करते हैं क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं इनके क्या अधिकार हो सकते हैं लेकिन यहां हमने बच्चों के अधिकारों के बारे में बताने की कोशिश की है ताकि बड़े लोग बच्चों के अधिकारों की कद्र कर सकें। बच्चों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के कानून में सबसे अधिक स्पष्ट व वृहद हैं। इसके 54 अनुच्छेदों में बच्चों को पहली बार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं :

1. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006, को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था।

यूनिसेफ द्वारा 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 को, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम-1929 के स्थान पर लाया गया था।

बच्चे की परिभाषा

वह पुरूष जिसकी उम्र 21 वर्ष और वह महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बच्चे की श्रेणी में रखा गया है।

2. भारत में बच्चों से संबंधित सबसे अधिक वाद-विवाद वाला अधिनियम 'बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम', 1986 है। इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चे कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ वे काम नहीं कर सकते हैं।

3. शिक्षा का अधिकार

68वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-ए को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

4. बाल तस्करीः यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी देश के भीतर या बाहर शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहन, स्थानांतरित या आश्रय प्रदान किया जाता है तो यह बाल तस्करी के अपराध के अंतर्गत आता है।

5. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 भारत में किशोरों के न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है। इस अधिनियम को 2006 और 2010 में संशोधित किया गया है। 2015 में जन भावना को देखते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इस बिल में संशोधन किया गया और किशोर की अधिकतम उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया।

6. बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2012: भारत में 53 प्रतिशत बच्चे किसी-न-किसी रूप में बाल यौन शोषण का सामना करते हैं। अतः भारत में इस अधिनियम को पुरूष और महिला दोनों के लिए लागू किया गया है। पोर्नोग्राफी के संबंध में, यह कानून बच्चों के सामने या बच्चों को शामिल करने वाली पोर्नोग्राफिक सामग्री को देखने या संग्रह करने को अपराध मानता है। यह अधिनियम बाल यौन दुर्व्यवहार को दंडनीय बनाता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

मिर्गी क्या और उपचार

मिर्गी दो तरह की होती है। कुछ मरीजों के दिमाग के एक हिस्से में दौरा पड़ता है, तो कुछ मरीजों को दिमाग के पूरे हिस्से में। अगर समय पर मरीज को इलाज मिल जाए तो 2 से 3 साल दवा खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। 20 से 30 प्रतिशत मरीजों को जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है जबकि 10 से 20 प्रतिशत मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मरीज को अपनी स्थिति के बारे में डॉक्टरों व परिजनों से छिपाना नहीं चाहिए। बेहतर इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।

मिर्गी के लक्षण

- बात करते हुए दिमाग ब्लैंक हो जाना, मांसपेशियों का अचानक फड़कना
- तेज रोशनी से आंखों में परेशानी होना, अचानक बेहोश हो जाना
- अचानक से मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देना

मिर्गी के प्रमुख कारण

- सिर पर चोट लगना, दिमागी बुखार आना
- दिमाग में कीड़े की गांठ बनना, ब्रेन ट्यूमर व ब्रेन स्ट्रोक होना
- शराब या नशीली दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना

दौरा पड़ने पर इन बातों का रखें ध्यान

- दौरा पड़ने पर रोगी को सुरक्षित जगह पर एक करवट लेटा दें
- कपड़े ढीले करें, खुली हवा में रखें और आसपास भीड़ न लगाएं
- सिर के नीचे मुलायम कपड़ा रखें, दौरे के समय रोगी के मुंह में कुछ न डालें

ऐसे करें बचाव

मिर्गी ज्यादातर युवाओं में देखी जाती है। पर्याप्त नींद, कच्ची सब्जियों से परहेज, साफ पानी से धुली सब्जियों को छीलकर खाने से मिर्गी से बचा जा सकता है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

12वीं के बाद करियर विकल्प

यदि आप 12 वीं कक्षा के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा या फिर आपके जानने वाले, माता पिता या रिश्तेदार आपसे अवश्य पूछते होंगे कि 12 वीं के बाद क्या करना है ? किस स्ट्रीम में जाना है ? आदि, आदि। अधिकांश छात्र 12 वीं में ही तय कर लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है? किस स्ट्रीम का चुनाव करना है या फिर किस करियर फील्ड में जाना है आदि। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी तक यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें भविष्य में क्या करना है? करियर का कौन सा फील्ड उनके लिए सही रहेगा ? इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूज्ड रहते हैं तथा कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण निर्णय क्यों है ?

12 वीं के छात्रों के लिए एक सही कोर्स का चुनाव करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि उनके इसी निर्णय पर मुख्य रूप से उनका करियर टिका होता है। अगर इस दौरान छात्र अपनी क्षमता, रूचि तथा प्रतिभा के विपरीत किसी गलत डोमेन का चयन कर लेते हैं तो इसका खामियाजा भविष्य में तो भुगतना ही पड़ता है छात्रों का अमूल्य समय भी बर्बाद होता है।

यह एक कठिन निर्णय क्यों है ?

एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने के साथ-साथ यह एक कठिन निर्णय भी है, विशेषकर आज कल के सन्दर्भ में तो और आजकल छात्रों के समक्ष कई करियर, कोर्स तथा स्ट्रीम के विकल्प मौजूद हैं और ये लगभग सभी अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप समान महत्व के हैं। कॉलेज में उपलब्ध कोर्सेज की इस विस्तृत श्रृंखला ने छात्रों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। वे दिन अब चले गए जब सिर्फ एक इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट और ऐसे अन्य कोर क्षेत्रों में ही अच्छे करियर ऑप्शंस थे। अब तो छात्रों के पास कुछ साल पहले की तुलना में बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। वे नए क्षेत्रों जैसे, टी टेस्टर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एथिकल हैकर्स के रूप में अपने करियर को नई दिशा देने में स्वतंत्र हैं। जबकि कुछ वर्ष पूर्व तक ये सभी कोर्सेज बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थे।

कैसे करें सही ग्रेजुएशन कोर्सेज का चयन

ग्रेजुएशन स्तर के लिए सही पाठ्यक्रम तय करना एक असंभव निर्णय लेने जैसा लगता है। 12 वीं के बाद सही कोर्सेज का चयन करते समय आपको यह पता होना चाहिए आपके लिए कौन से विकल्प बेहतर हैं तथा किस विकल्प में आप अपना बेहतर दे सकते हैं? इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का वर्णन किया जा रहा है-

अपनी रुचि का हमेशा रखें ख्याल

किसी भी कोर्स का चयन करते समय जिस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए वह है अपनी रुचि, जुनून, इच्छा तथा मनपसंद कार्यों की पहचान कर उस अनुरूप कोर्सेज का चयन करना। यदि आप पद सभी बातों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं तो आपको अपने लिए किसी सही कोर्स के चयन में दुविधा या परेशानी नहीं होगी। उदहारण के लिए यदि आप अर्कियोलॉजी लेना चाहते हैं लेकिन आपकी रूचि केमेस्ट्री में है तो आप कला संग्रह या फिर म्यूजियोलॉजी संग्रहालय सम्बन्धित) आदि आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन हो सकते हैं।

2. पाठ्यक्रम की समझ

इससे पहले कि आप किसी कोर्स का चयन कर उसका अध्ययन आरम्भ करे आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि आपके कोर्स की विषय वस्तु क्या है और यह किन किन क्षेत्रों को कवर करता है? किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अपने कोर्स के विषय में मौजूद सामग्रियों तथा सीनियर्स और फैकल्टी की मदद से उस विषय में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। जैसे कि कितना थ्योरी का पेपर है? कितना प्रैक्टिकल है ? किस तरह की टेक्नोलहजी का इस्तेमाल होता है ? आदि आदि। इसके लिए आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, दोस्तों तथा किसी सीनियर्स की राय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो उस फील्ड में पहले से ही कार्यरत हैं वे भी आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अगर तब भी बात न बने तो किसी करियर काउंसलर की सलाह अवश्य लें।

12 वीं के बाद उपलब्ध कुछ लोकप्रिय कॉलेज पाठ्यक्रम

12 वीं के बाद अक्सर भारतीय छात्र दो ही कोर्सेज इंजीनियरिंग और मेडिकल को करियर विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन अब नित्य नये नये उभरते विकल्पों की वजह से उनके समक्ष भी अब कई अन्य कोर्सेज का विकल्प मौजूद है। पुरानी अवधारणाओं को तोड़ते हुए छात्र अपनी प्रतिभा के अनुरूप इन नए ऑफ-बीट कोर्सेज का चयन कर उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं।

इंजीनियरिंग

12 वीं के बाद सबसे ज्यादा डिमांड वाला कोई कोर्स है तो वह है इंजीनियरिंग। एक प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से इस कोर्स की तरफ अधिकतम छात्र आकर्षित होते हैं। फीजिक्स, केमेस्ट्री तथा गणित विषय के साथ 12 वीं पास करने वाले छात्र इस कोर्स में एडमिशन लेने के पात्र होते हैं। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण यह कोर्स बहुत कॉम्पीटिटिव है। वैसे भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए इन कॉलेज के इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) है, जो देश भर में इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित एक आम इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। पिछले वर्ष लगभग 11 लाख छात्र जेईई मेन परीक्षा में शामिल हुए थे, यह छात्रों के बीच इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत है।

मेडिकल साइंस

इंजीनियरिंग के बाद, साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा विकल्प मेडिकल या मेडिसिन होता है। मेडिकल वस्तुतः जीवन और उसके चारों ओर की हर चीज का अध्ययन है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम ही है जहाँ मेडिसिन की पढ़ाई कर आप अपना सपना पूरा कर सकते है। 12 वीं के बाद मेडिकल साइंस स्टडीज के हिस्से के रूप में फार्मेसी, कृषि विज्ञान और प्राणीशास्त्र का अध्ययन भी किया जा सकता है। आजकल फार्मेसी में ग्रेजुएशन मेडिकल छात्रों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत उन्हें यह सिखाया जाता है कि दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, वे कैसे काम करते हैं ? नशीली दवाओं की प्रतिरक्षा, उसका रोगी पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।

कॉमर्स

11 वीं और 12 वीं कक्षा में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम विकल्पों में से एक है। इसके अंतर्गत सरकारी कानूनों के अनुसार कंपनियों के वित्तीय मामलों की सम्पूर्ण जानकारी सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और लेखा परीक्षा के माध्यम से कराधान, वित्तीय लेनदेन आदि विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है।

चार्टर्ड एकाउंटेंसी के अलावा, कॉमर्स छात्रों के लिए उपलब्ध अन्य लोकप्रिय पाठ्यक्रम विकल्प बिजनेस मैनेजमेंट (बीबीए), बीकॉम, बीकॉम (एच), अर्थशास्त्र (एच), सीएस, लॉ, ट्रेवल एंड टूरिज्म आदि में ग्रेजुएशन है। इन कोर्सेज की मदद से निवेश बैंकर, ब्रांड मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और अन्य प्रतिष्ठित पदों के रूप में एक प्रतिष्ठित करियर बनाया जा सकता है। लेकिन 12 वीं में बिना गणित सब्जेक्ट लिए कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र आगे चलकर कुछ उपलब्ध कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं।

आर्ट्स

आर्ट्स या ह्युमेनिटिज के अंतर्गत अधिक संख्या में भिन्न भिन्न कोर्सेज की सुविधा के कारण छात्रों को अपनी रूचि के अनुसार विषय चुनने की अधिक आजादी होती है। पिछले कुछ वर्षों से आर्ट्स के प्रति छात्रों का झुकाव बढ़ा है। आजकल अधिकतर छात्र आर्ट्स का चयन कर रहे हैं।

मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, विज्ञापन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, रंगमंच आदि विषयों में से आर्ट्स के स्टूडेंट्स किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं।

प्रवेश परीक्षा

12 वीं के बाद छात्रों की मुख्य चिंता आगे चलकर किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने की होती है।

आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या किसी अन्य कोर्सेज के लगभग सभी स्ट्रीम्स के संबंधित डोमेन में प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं का अपना एक अलग सेट होता है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र इन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होते हैं।

Ayodhyawasis never burnt cracker : Criminality in flexibility

This year Delhi government heaved a sigh of relief when media reported that the level of pollution in NCR was the least as per the data of the last three years. People are discouraged to visit Delhi as the pollution level is still very high. Such a situation occurs every year during Diwali, when school children and people in general use masks while going out. Delhi is ranked as one of the highly polluted cities across the world and the system is becoming insensitive and perhaps a victim of amnesia.

The news reports keep on flashing during the season and the race of life and the style of the government remains unchanged. Everyone gets conscious when the pollution is the talk of the town for some time and then people eventually forget all about it. The Government of India and the Government of Delhi both seem handicapped in spirit to combat the pollution even during the festive season.

When interacting with the common people about the no-use of the crackers, they start confronting with the logic that only the Hindu festivals and rituals are targeted which lead to cultural erosion. Here we have failed to spell out the fundamentals of religions to every community. The excessive freedom to practice whatever useful or useless postulated or propagated is sowing seeds of crime. The so-called secular status misquoted by many political creatures and contractors of communities became instrumental in permitting the people to "enjoy their ignorance" which is now a cause of creating multiple social, economic, political and environmental problems. The government always restricted itself from intervening in this area and remained a silent spectator while being well-aware of the good and bad that affect people.

Apart from Maharshi Balmiki and Bhakt Tulsi Das, there have been a number of researches on Ramayana and thousands of scholars have narrated Ramayana in multiple languages. No one has ever established the fact that the crackers were burnt by Ayodhyawasis to welcome Rama, Sita and Lakshmana after killing Ravana. It is said and believed that the Ayodhyawasis illuminated Ayodhya with Deepaks and this festival of lights rightly represents the triumph of truth over ignorance and good over bad. Then why are we not able to inspire people to stop burning crackers which are nothing but sophisticated mini bombs.

On the other hand, why cannot we stop production of crackers through administrative actions or by enacting laws or religiously implementing the verdict of the court?

Every year during or after Diwali, the reports of fire incidents, physical hazards to people, rendering many homeless keep on getting wider space in media. And this occasion also sees rampant gambling and numerous social evils committed by people in inebriated condition; the system does not take it seriously and things keep on going like always.

Until the rational character of any religion is forcibly imposed by the state, the citizens will keep on moving in the darkness, which is perhaps a violation of the very objective of the formation of the state, which is to ensure the Wellbeing of its Citizens.

When we can impose heavy penalties on violation of traffic rules, we can ensure administrating polio drops to each and every child in every corner of the country, then how can we afford to remain the silent spectators when it comes to social, religious and environmental concerns.

The secular character of the Constitution seems to have been misinterpreted to not to enter in the domain of the faith and the style of worship practised by people. Whereas it should have been to rationalise the practices of every faith and allow people to practice any rationalised practices as per their will based on three universally acknowledged fundamental principles viz.

(a) No action is valid if it disturbs the environmental equilibrium as the earth needs to be saved for future generations.

(b) No action is valid if it promotes the violence or torture to any living being as the objective of the religion cannot be the enjoyment at the cost of others. It has to be based on ***"Sarve Bhavantu Sukhinah"*** **सर्वे भवंतु सुखीनः**

(c) No action is valid if it promotes irrational thoughts and retrogressive postulates.

When the practice of so-called religious thoughts will be made to pass through the above 3 principles, the filtered ones will be something worth adopting. This needs legislature backing followed by military-styled enactment.

An individual of the civilisation of 21st century needs to overcome the so-called dogmas i.e. burning crackers- the heights if irrationality; sacrificing animals in religious places and ceremonies- the heights of ignorance and torturing animals before killing- the heights of cruelty on earth.

In fact, the real objective and definition of "religion" needs to be propagated and people should be made aware that religion is a laboratory of overcoming human limitations towards liberty and the spirituality is the principle experimented in the laboratory.

Without this, we will only be sowing criminality through our excessive flexibility.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

STATE OF MIND

Fast development, advance growth and competition in every sector is the rule of the day. Most commonly used word is competition. Competition among the INDUSTRIES, PRODUCTS, INDIVIDUALS, SOCIETY ETC.

It is writ large and bold in front of us that the postulate of "Survival of the fittest" of Darwin's theory has come to manifest everything among us.

To some extent competition is good otherwise one may become dull, inactive. Progress is the outcome of change and competition. It is the change in the surrounding which motivates us to work or to be active.

Everyday new techniques are being used. Things of yester years ago have become absolute. The rate of redundancy has accelerated with the march of science, specifically the information technologys.

Do we thumb that it is possible for everyone to be successful in such cut throat competition ?

Different survival techniques are being used. Fair or UNFAIR, FIGHT or FLIGHT. Such an environment can only lead to lack of happiness and contentment. Children from the very beginning are learning the inappropriate ways of survival because they are coaxed regularly to perform better. Bigger and Bigger goals are put in front of them without even considering their state of mind, capabilities ,interests, hobbies, etc.

Regardless of continued pressure from parents and peers can make, them prone to frustration, aggression etc.

This inevitably leads to gap between the aspiration and achievement of goals set for one by himself or others. Most of the people are dissatisfied with their lives and feel depressed fearful, anxious or angry. Recourse to adventurism can distort the path of unfulfilled life if adventure is not sufficiently cautious.

We are living in a society and during interaction we develop certain needs which can be social status, self esteem, affiliation, etc. To achieve these we have to modify our ways. It may be possible that all our efforts step by step, help us to reach the ultimate goal. Since competition, fair or foul, manifests all around the success rate will obviously be very low. In such a situation, what is an individual's reaction, positive or negative will only help one to deal with the crisis.

FIGHT or FLIGHT OR RESIGN are the three ways to face the situation. One could be prepared to tackle each and every situation; even in the adverse circumstances i.e. fight, or run away ,i.e., flight. Both the situation create stress which can result in either aggression or frustration.

The last option of resigning to the situation leaves little doubt as to weather we living beings are not different from the non living ones.

When someone is not in a sound and meaningful good state of mind, then one connects every situation with oneself. There is tendency to personalize everything. If distortion of thinking is allowed to continue for a longer time, one becomes involved in oneself and crowding of thoughts take place, mind starts wandering. This is the stage when negative emotions start affecting the body. All vital system of the body i.e immune system, Hormonal system, nervous system, circulatory system get disturbed, ultimately resulting into ailments of the body or mind.

The remedy lies in the converse i.e positive thinking . In present circumstances when each and every mind is sick , how can you change the society to a healthier format and Fabric unless every one takes oath to change oneself first.

The solution to the above narrated conundrum cannot be realized in "material" methodology but in spiritual regime. And hence we must have something by way of holding on to, which is " Faith ". This and only this can make us move on to the path of positive thinking and looking for something positive in every occurrence around us.

(Guest Writer) Ajay Vasishth

लेखक के निजी विचार है, इसमें 'द रीव टाइम्स' की सहमति आवश्यक नहीं है

फूल बरसाने की संस्कृति में होती है पत्थरों की बरसात

प्रथाओं के नाम पर हो रहा है खूनी खेल

क्या देवी-देवता इंसानों के खून की चाह रखते हैं ?

वैज्ञानिक युग में हम आज चांद और मंगल पर जीवन की तलाश कर रहें हैं ताकि इंसान के क़दम ही नहीं वहां रहने की अनुकूल व्यवस्था के कोई चिन्ह या प्रमाण प्राप्त हो जाए। 21वीं सदी विज्ञान युग में चमत्कार की तरह है। ऐसे में आज भी भारत अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को सहेजे हुए हैं जो इसकी महानता को प्रदर्शित करता है। लेकिन परंपराओं और प्रथाओं के नाम पर आज भी कुछ अविश्वसनीय बातें सोचने पर विवश करती है। ये प्रथाऐं वैसे तो कई प्रकार की हैं लेकिन एक प्रथा ऐसी भी है जिसमें लोग एक-दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं और जब तक किसी का खून नहीं निकाल लेते तब तक पत्थर मारते रहते हैं। इस प्रथा पर बुद्धिजीवियों का मत तो ये है कि ये कौन सा युग है जिसमें इंसान, इंसान को पत्थर मारता है। इस परंपरा का निर्वहन भारत जैसी विश्वबंधुत्व प्रथा पर चोट की तरह है।

दीपावली के दूसरे दिन होता है धामी का पत्थर खेल मेला

शिमला ज़िले के आख़िरी छोर पर सोलन ज़िला की सीमा से सटे धामी क्षेत्र में एक सती चौक है। उस सती चौक के दोनों ओर दो पहाड़ियों पर दीपावली के दूसरे दिन एक बड़ा मेला होता है जिसमें हज़ारों लोग एकत्रित होते हैं। मेले में सुन्दर बाज़ार सजता है। लोग पूरे वर्ष अगर नहीं मिल पाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों के लोग अवश्य ही इस मेले में पंहुचते हैं और मिलते हैं। लेकिन इतना ही आकर्षण नहीं है इस मेले का। इस मेले का मुख्य आकर्षण है पत्थर का खूनी खेल जिसे दो गुट दोनों पहाड़ियों पर खड़े होकर पूरी शिद्दत से खेलते हैं, इस बात से अनभिज्ञ कि किसी की जान तक जा सकती है। इसे दो गुटों के बीच का संघर्ष कहें या प्रचलित प्रथा का ही अंग लेकिन ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये दोनों गुट सती चौक पर एकत्रित होते हैं और फिर शुरु होता है खुनी खेल का वो दृश्य जिसे आज पढ़ी-लिखी पीढ़ी सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकती है। दोनों गुट पूरी ज़ोर आजमाईश के साथ एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को जानते नहीं। दोनों गुटों में दोस्त भी हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि पत्थर मारकर सिर फोड़ने को आतुर ये लोग कुछ नहीं देखते। इसमें एक पक्ष कटेडु और दूसरा जमोगी का होता है। ये खूनी खेल तब तक चलता है जब तक कि किसी का सिर न फट जाए या खून न बहने लगे। एक पक्ष में जिसको पहले पत्थर लगता है उस पक्ष के उस व्यक्ति को सती चौक पर खून से तिलक किया जाता है तथा पहाड़ी पर स्थित भद्रकाली मां के मंदिर में ले जाकर वहां खून का तिलक किया जाता है। उसके बाद ही यह खेल बंद होता है। हज़ारों लोग इस खेल के मूक दर्शक होते हैं। इस परंपरा को अनेक वर्षों से जस के तस आगे बढ़ाया जा रहा है। धामी में ही कुश्ती का भी एक प्रसिद्ध खेल होता है जिसमें बाहरी राज्यों से भी पहलवान आते हैं और इस कुश्ती की लोगों में दिनोंदिन खूब मशहूरी भी हो रही है। हालांकि यह मेला कुछ समय पहले ही शुरु किया गया था लेकिन पत्थर का खेल मेला पारंपरिक मेलों की श्रेणी में आता है क्योंकि यह एक पुराने समय से चला आ रहा है। दीवाली के दूसरे दिन ये खून की दीवाली खेली जाती है जिसका समर्थन करना रुढ़िवादिता ही कहा जा सकता है।

कालीहट्टी का पत्थर खेल मेला भी पारंपरिक

धामी के खेल के मेले के 10 दिन बाद दयोठन के अगले दिन धामी से 10 से 12 किमी. दूर कालीहट्टी में भी एक प्राचीन पत्थर खेल मेला होता है जिसमें दो वर्ग एक-दूसरे पर जमकर पत्थर मारते हैं। यहां एक प्रसिद्ध और पारंपरिक मां काली का मंदिर है जिसमें हज़ारों की आस्था जुड़ी हैं। यहां दयोठन त्यौहार जो दीपावली के 11 दिन बाद आता है के अगले दिन दो गुट आपस में भिड़ते हैं तथा जमकर पत्थरों से प्रहार करते हैं। यहां दोनों ओर पहाड़ी हैं और बीच में मां काली का मंदिर है। मंदिर के एक तरफ परमार वंश मलांगड़ और दूसरी ओर चौहान वंश जिन्हें रंगोलड़ कहते हैं, पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में पत्थरों की बरसात शुरु हो जाती है। जब तक किसी का सिर फुट्टव्वल न हो जाए कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटता। जिस पक्ष के व्यक्ति में पत्थर लग जाता है तो दोनों हाथ खड़े करके खेल को रोकने का संकेत किया जाता है। जिसे पत्थर लगा है उसको मां काली के मंदिर ले जाकर उसके खून का तिलक किया जाता है। इस मेले में भी दूर-दूर से लोग आते हैं। मेले में तरह-तरह के पकवान और सामान सजा होता है तथा लोग जमकर खाते-पीते हैं। इसके अलावा महिला-बच्चे खरीददारी करती हैं। लेकिन जितनी देर यह पत्थर का खेल होता है उतनी देर तक सब कुछ थम सा जाता है। इस खेल में पहले बड़े लोग हिस्सा लिया करते थे लेकिन विडंबना देखो अब युवा भी इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और जमकर पत्थरबाजी करते हैं।

मान्यता के नाम पर नृशंसता

अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना और अनुसरण करना हर युग में हर पीढ़ी का नैतिक कर्तव्य भी है। लेकिन कुछ परंपराऐं यदि इंसानी दुश्मन ही बन जाए तो उसका निर्वहन करना मूर्खता कही जाती है। यहां आज भी इस मान्यता को माना जाता है कि दोनों गुटों को एक दूसरे पर पत्थर मारने ही पड़ते हैं वरना दोष लगता है और मां का प्रकोप सहना पड़ता है। बहुत समय पहले यहां मानव बलि देने की प्रथा थी। राजा की मृत्यु होने पर रानी ने सती होने का निर्णय लिया लेकिन रानी मानव बलि को रोकना चाहती थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सती होने के बाद रानी ने माता से बात की और फिर कहा कि मानव बलि को बंद कर दिया जाए। इसके बदले में कुछ समय तक निर्जीव पशुओं की बलि दी जाती रही। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि माता काली ने इसे स्वीकार नहीं किया और इससे महामारी फैल गई। माता को मानव रक्त ही चाहिए था और ऐसा न करने पर माता ने महामारी फैला दी। अब इसका विकल्प इस प्रकार पत्थरों का बेहड़ यानि एक-दूसरे पर पत्थर मारकर रक्त चढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी की आड़ में खूब प्रचार-प्रसार और ढोल-नगाड़ों के साथ इंसान एक दूसरे पर उसका रक्त बहाने के लिए पत्थर मारता है। और खेलते-खेलते यह खेल इतना भयानक हो जाता है कि कई बार इसके परिणाम गंभीर हो जाते हैं। यहां यह सोचना आवश्यक है कि क्या हम मान्यताओं और परंपराओं के नाम पर पिशाची संस्कृति को अपना रहे हैं। इन्हीं मान्यताओं के नाम पर कभी किसी की आंख फट जाती है कभी किसी का सिर। कभी कोई गंभीर चोट लग जाती है। इतना ही नहीं, कभी तो जान पर भी बन सकती है। लेकिन इसका विरोध नहीं किया जाता है क्योंकि इससे देवी का प्रकोप होगा या भगवान कोई अनिष्ट कर देगा। क्या ये मान्यताऐं इंसान की दुश्मन हैं या इंसान की महान संस्कृति की पैरवी करती हैं ? ये प्रश्न आज के संदर्भ में वाज़िब है और इसका उत्तर तलाशना भी उतना ही वाज़िब है।

तर्क देकर ग़लत सही नहीं हो सकता

इस परंपरा का निर्वहन तर्क के आधार पर किया जाता है। जब इस बाबत पूछा जाता है कि इस प्रकार एक-दूसरे पर पत्थर फेंकना सही है क्या, तो उसका उत्तर यही होता है कि पत्थर न मारे गए तो मां का प्रकोप होगा और इससे बचने के लिए यह खेल आवश्यक है। मां खून मांगती है.....वगैरह.. वगैरह....। दूसरा तर्क यह है कि जिसे पत्थर लगता है उसे मां के आशीर्वाद से बिलकुल भी दर्द नहीं होता है। बल्कि वो खुशी से झूम उठता है। कई बार कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा कि जिसे मां चाहे उसे चुनती है और उसी का रक्त मंदिर में मां को चढ़ता है। इन तर्कों को आधार बनाकर दो गुटों के लोग जेबों में पत्थर भरकर एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं। क्या इन तर्कों को मान्यता देते हुए इस खेल को सही ठहराने की ग़लती की जा सकती है।

इन तर्कों का तोड़ प्रथम उदाहरण के रुप ये है कि बचपन से ही मैंने इस मेले में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। एक बार जब दनादन पत्थर बरस रहे थे तो वहीं पास एक युवक को पत्थर लग गया। वह युवक भी उन्हीं में से एक टोली से संबन्धित था। पत्थर लगते ही पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। एक बड़ा पत्थर दाहिनी आंख के बिलकुल ऊपर गहरा सुराख़ कर गया। खेल को रोकने का संकेत किया गया। उस युवक को पुजारी के पास ले जाया गया तथा पुजारी उसे मां के मंदिर में ले गए। उसके रक्त से मां को तिलक किया गया। किसी ने युवक से पूछा कि क्या आपको दर्द हो रही है ? वहां खड़े पंडित ने कहा कि कितनी भी गहरी चोट लग जाए पर पीड़ा नहीं होती। यही तो मां का चमत्कार है। इस पर घायल युवक का सब्र टूट गया। उसने कहा कि तुम अपना सिर फोड़ो और मुझे बताओ कि पीड़ा होती है कि नहीं ? उस युवक को चक्कर आ रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे कई टांके लगे जिनसे उभरने में कई दिन लग गए। उस युवक का नाम था लोकेश। इसी प्रकार यहां एक बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या देवी-देवता इंसान के खून से तृप्त होते हैं ? क्या कोई भगवान या देवी या देवता किसी इंसान का रक्त मांग सकते हैं ? यदि हमारी आस्था है कि ईश्वर हम सभी के पालनहार है और हमें सद्मार्ग पर चलकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्ठा करनी चाहिए तो क्या कोई भगवान कभी एक दूसरे पर पत्थर मारने की चाह रख सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के खून के प्यासे बनाने के लिए कह सकते हैं?

हिंसा से अहिंसा व भ्रम से यर्थात् का मार्ग दिखाते हमारे अराध्य

यदि हम अपने ग्रन्थों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धार्मिक सामग्री को अध्ययन करें तो उसका निचोड़ यही है कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करें, अहिंसा का पालन करें, भाईचारा और सद्भाव की पद्धति पर चलकर जीवन को सफल बनाने में लगे रहें। हमारे देवी-देवता हमारे अराध्य हैं और हमारी शक्ति का आधार भी। इनके नाम पर प्रचलित कुछ प्रथाओं के नाम पर इस प्रकार के आयोजन क्या सर्वोचित माने जा सकते हैं ? ईश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं चाह सकते। हमारी परंपरा और संस्कृति तो **'सर्वेभवन्तुसुखिनः सर्वेसंतुनिरामया सर्वेभद्राणिपश्यंतु मा कश्चिद्दुःखभागभवेत्'** की निर्लेप और जीवकल्याणकारी पद्धति की द्योतक रही है। क्या हमारे पूर्वज़ जिन्हें हम देवता सम्मान अराधना करते हैं, वो कभी किसी जीव की हत्या या मानव रक्त को स्वीकार करने की बात कह सकते हैं ? क्या देवी-देवता बेजुबानों और उन्हीं की संतान यानि मानव का रक्त कभी मांग सकते हैं ? कदापि नहीं ! हम सभी इन्हीं देवी-देवताओं की संतान है और संतान का रक्त लेने की बात कभी भी पाच्य नहीं हो सकती है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम इसे खेल की भावना से देखते हैं और इस प्रथा को यथावत रखना चाहते हैं। दरअसल, पशुओं की बलि का प्रचलन भी तथाकथित जीभ का स्वाद है जिसके लिए देवी-देवताओं

की आड़ ली जाती है। लाखों पशुओं के रक्त से देवस्थल नहाए जाते हैं और उसके बाद उन पशुओं के मांस को इंसान चटकारे लेकर खाता है। इसी प्रकार आज भी कई जगहों पर बच्चों को कड़ी और नृशंस यातनाऐं दी जाती है जिसके पीछे मान्यता है कि इससे बच्चों के ग्रह शांत होते हैं। लोग सड़क पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों और सांडों को भगाया जाता है। इससे उनके कष्ट दूर होते हैं ! ये सभी आडंबर हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं इसका आकलन करना वर्तमान में अति आवश्यक है।

मेले का प्रारूप बदल कर फूल बरसाऐं

पत्थर मार कर किसी का सिर, आंख फोड़कर उसका खून देवस्थल में चढ़ाने की नृशंस और अमानवीय परंपरा को बंद करने में आज भी यदि मुश्किल आ रही हो तो इसका दूसरा विकल्प ये भी है कि दोनों ओर के पक्ष हर बार किसी एक व्यक्ति को चुनकर अंगुली से रक्त निकाल कर देवस्थल में चढ़ाऐं न कि पत्थर मारकर एक दूसरे को लहुलुहान करें अथवा जान जोख़िम में डालें। हम फूल बरसाने वाले देश के नागरिक हैं, पत्थर मारना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। देवी-देवताओं के प्रकोप को बताकर डराने से बेहतर है कि इन देवताओं की अराधना पुष्प और दीपों से करें। अपने आचरण और व्यवहार से मानवसेवा में जीवन का ध्येय समझें। ये देवगण हमारी खुशहाली और सभ्य समाज से प्रसन्न होते हैं न कि हमारे रक्त से। ये एक ऐसी हिंसा है जो सार्वजनिक रुप से की जा रही है और इस पर न तो कानून की कोई पकड़ है और न ही माननीय न्यायालय की। हिमाचल में भैंसों को लड़ाया जाता रहा है। इसे भी परंपरा और देवताओं से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन माननीय न्यायालय की रोक के बाद अब यह खेल बंद कर दिया गया और सख़्त आदेश दिए गए कि बेजुबानों को इस प्रकार कहीं भी लड़ाया गया तो इसके लिए दोषियों को दंडित किया जाएगा। आज ये भैंसों का खेल बंद है तो कौन का प्रकोप देवी-देवताओं ने हम पर किया है ? इसी प्रकार आज यह सोचने की आवश्कता है कि क्या पत्थर मारकर हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं अथवा अपने साथ किसी की जान को जोख़िम में डाल रहे हैं। मेले को मिलन, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, देवपूजा, ग्रामीण खेलों से जोड़कर मनाने की आवश्यकता है.....खून की होली खेलने से नहीं। नई पीढ़ी को देवताओं के आशीर्वाद और आस्था से गुणवान बनाकर रुढ़िवादिता और हिंसा के वातावरण से मुक्त कर राष्ट्रनिर्माण में तैयार करने के लिए संकल्पबद्ध करने की आवश्यकता है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

मंडी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का खर्चा वहन करेगा–केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से जिला मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने शिमला, कांगड़ा और कुल्लू हवाई अड्डों के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की।

यह निर्णय भारत सरकार के नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि शिमला और कांगड़ा के हवाई अड्डों के विस्तार की लागत को केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय वहन करेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक दल शीघ्र ही कुल्लू तथा मनाली हवाई अड्डों के विस्तार के सर्वेक्षण के लिए दौरा करेगा।

उन्होंने कहा कि उड़ान-2 के तहत नागर विमानन मंत्रालय प्रदेश में छः प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण तथा परिचालन की लागत के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने इसके अतिरिक्त उड़ान-1 के अंतर्गत वर्तमान सेवाएं पहले की तरह जारी रहेगी।

सचिव, संयुक्त सचिव और महानिदेशक नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन हिमाचल प्रदेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

सीएम के प्रधान सचिव ने केंद्रीय मंत्रियों से इन्वेस्टर मीट में सहयोग के लिए किया आग्रह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने नई दिल्ली में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बीते सप्ताह भेंट की। उन्हें धर्मशाला में 7 और 8 नवंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अनुराग ने 7 नवंबर को अपनी भागीदारी की पुष्टि की तथा संयुक्त अरब अमीरात के साथ होने वाले सत्र की अध्यक्षता करने को सहमति जताई।

संयुक्त अरब अमीरात इस आयोजन में भागीदार देश है। संजय कुंडू केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले। उन्हें इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में बताया। उन्होंने इस आयोजन के लिए मंत्रालय से समर्थन देने के लिए भी अनुरोध किया।

RISING HIMACHAL GLOBAL INVESTORS MEET 2019

मंत्री ने मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग और आयोजन के व्यापक प्रचार का आश्वासन दिया। संजय कुंडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे तथा आकाशवाणी के महानिदेशक एफ. शहरेयार से मुलाकात की। दोनों ने इस मेगा इवेंट के पूर्ण समर्थन तथा व्यापक प्रचार का आश्वासन दिया।

अपनी सोसायटी को भी जमीन नहीं बेच सकेंगी धार्मिक संस्थाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में जमीन खरीदने के बाद धार्मिक संस्थाएं इसे अपनी ही किसी सोसायटी या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बेच सकेंगी। राज्य सरकार ने धारा 118 के तहत मिले राधास्वामी सत्संग के एक आवेदन को रद्द कर दिया है। सरकार ने हमीरपुर के भोटा अस्पताल की राधास्वामी सत्संग की जमीन की गिफ्ट डीड इसी की सोसायटी के नाम करने की अरजी ठुकरा दी है।

हाल ही में राधास्वामी सत्संग ने सरकार को मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत एक आवेदन किया। इसमें निवेदन किया कि राधास्वामी सत्संग की एक सोसायटी भोटा में अस्पताल चला रही है। इस सोसायटी के पास बहुत पहले यह जमीन लीज

पर दी गई थी। अब इसकी गिफ्ट डीड को इसी सोसायटी के नाम किया जाए।

सरकारी स्तर पर विचार करने के बाद इस आवेदन को धारा 118 के तहत अनफिट पाया गया है और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजने की जगह रद्द कर दिया गया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि 17 जनवरी 2014 को लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 5 (आई) में संशोधन के बाद एक प्रावधान किया है कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए हिमाचल में जमीन खरीद की कोई सीलिंग तो नहीं रहेगी, लेकिन यह शर्त भी रहेगी कि यह जमीन आगे किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को बेच नहीं पाएंगी और न ही लीज पर दे पाएंगी।

इसी शर्त के कारण राधास्वामी सत्संग के आवेदन को रद्द किया गया। चूंकि जमीन इस प्रावधान से पहले ही सोसायटी को लीज पर दी गई है, इसीलिए यह लीज पर रह सकती है। सरकार की ओर से इस संस्था को यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह लैंड सीलिंग एक्ट की अवहेलना होगी। ऐसा करने से पहले लैंड सीलिंग एक्ट की धारा-5 (आई) में संशोधन करना होगा। यह संशोधन बिल पारित करने या अध्यादेश लाने से होगा।

हिमाचल में पंचायती राज उपचुनाव की अधिसूचना जारी, ये रहेगा शेड्यूल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। ग्राम पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों, पंचायत वार्ड सदस्यों के जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों की 247 रिक्त सीटों के लिए ये चुनाव 17 नवंबर को होंगे। संबंधित क्षेत्रों में मौत होने या किसी अन्य कारण से ये सीटें खाली हो गई थीं। इसी के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी उपायुक्तों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। ये चुनाव कुल 247 सीटों के लिए हो रहे हैं। इनमें प्रधानों की 20, उपप्रधानों की 22 और वार्ड सदस्यों की 196 सीटें हैं। जिला परिषद की एक और पंचायत समिति की आठ सीटें हैं। अगले साल ग्राम पंचायतों के आम चुनाव भी हैं, मगर उससे पहले वैधानिक अनिवार्यता को देखते हुए ये चुनाव करवाए जा रहे हैं।

ये रहेगा उपचुनाव का शेड्यूल

मतदान केंद्रों की सूची एक नवंबर 2019 या इससे पहले प्रकाशित करनी होगी। नामांकन पत्र एक, दो या चार नवंबर 2019 को 11 से तीन बजे के बीच तय स्थानों पर भरने होंगे। नामांकन पत्रों की पांच नवंबर 2019 को 10 बजे के बाद स्क्रूटिनी होगी। नामांकन वापसी सात नवंबर को 10 से 3 बजे के बीच होगी।

चुनाव चिन्ह भी सात नवंबर को मिलेंगे। मतदान 17 नवंबर को सात बजे से तीन बजे के बीच होगा। पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए मतगणना चुनाव के तत्काल बाद होगी और उसी दौरान नतीजे भी आ जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 18 नवंबर को नौ बजे से शुरू होगी।

किस जिले में कितनी सीटों के लिए उपचुनाव

जिला बिलासपुर में 11, चंबा में 17, हमीरपुर में 27, कुल्लू में 13, कांगड़ा में 53, लाहौल स्पीति में 4, मंडी में 48, शिमला में 14, सिरमौर में 17, सोलन में 18 और ऊना में 25 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं।

औद्योगिक ढांचा बनाने पर प्रदेश सरकार निवेशकों को देगी रियायतें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और औद्योगिक ढांचा बनाने के लिए सरकार निवेशकों को रियायतें और प्रोत्साहन देगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में सरकार निवेशकों के लिए साझा औद्योगिक और सोशल ढांचा तैयार करने और इन्हें अपग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी।

साझा एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कामगार महिला और पुरुष हॉस्टल, स्कूल, जांच केंद्र, जांच लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, हेल्थ केयर, टूल रूम, मनोरंजन सुविधाएं और सरकार से मान्यता प्राप्त अन्य औद्योगिक और सामाजिक केंद्रों के लिए सरकार बढ़ावा देगी। ऐसे निवेशकों को माइक्रो, लघु और मध्यम श्रेणी के निवेशकों को नई नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार औद्योगिक ढांचा और थीम पार्क बनाने को अविकसित सरकारी जमीन लीज पर निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराएगी।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेशक औद्योगिक पार्कों को विकसित करना चाहते हैं तो इन्हें निजी क्षेत्र में स्वयं चिह्नित या खरीदी भूमि में विकसित करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा आवंटित जमीन में भी ये पार्क तैयार किए जा सकते हैं।

इसके लिए निवेशक कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी ले सकेंगे। औद्योगिक पार्क विकसित करने को ए, बी और सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में यह उपदान कुल खर्च राशि का 25,

40 और 50 फीसदी तक दिया जाएगा। यह ए, बी और सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 15 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़ तक की सीमा रहेगी।

सरकार ने थीम पार्क विकसित करने को अहम क्षेत्रों का चयन किया है। एग्रो, हर्बल, ज्ञान, फूड, आईटी, इलेक्ट्रिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, फार्मा, टेक्सटाइल और अन्य पार्क विकसित किए जाने हैं।

अब बिना एनओसी के पास होंगे भवनों के नक्शे, लोगों को मिलेगी राहत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में अब भवनों के नक्शे पास कराने के लिए पहले से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग आवेदन के मात्र 30 दिन के भीतर नक्शा पास कर देगा। इसके बाद भवन निर्माण किया जा सकेगा। कंपलीशन सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा, जब विभागों का एनओसी दिया जाएगा। इन्वेस्टर मीट के चलते उद्योगों और बिल्डरों को रिझाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरकार के इस फैसले से आम लोगों को भी घर बनाने में राहत मिलेगी। टीसीपी आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाने जा रही है। पहले लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए कई विभागों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। टीसीपी का तर्क है कि लोग मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं। समय पर नक्शा पास न होने पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है।

टीसीपी एरिया में अभी लोगों को नक्शा पास कराने से पहले पर्यावरण, फॉरेस्ट, आईपीएच, बिजली बोर्ड आदि विभागों से एनओसी लेने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता है। नियम कड़े होने से बिल्डर कॉलोनियों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब आवेदन के दौरान लोगों को प्लॉट के चित्र के साथ सिर्फ ततीमा और जमाबंदी देनी होगी।

टीसीपी कर्मचारी सिर्फ एक बार मौके का निरीक्षण करेगा। उसके बाद निर्धारित समय पर लोगों को नक्शा पास करके दिया जाएगा। अभी लोगों को नक्शा पास कराने के लिए टीसीपी कार्यालय में प्लॉट के 7 चित्र देने पड़ते हैं। उसके बाद टीसीपी का जूनियर इंजीनियर मौके का निरीक्षण करता है। यह मानचित्र सभी विभागों में मंजूरी के लिए जाता है।

डिपो में कैल्शियम–आयरन युक्त मिलेगा तेल और आटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में पौष्टिक तत्व वाली खाद्य वस्तुएं मिलेंगी। अभी डिपो में साधारण खाद्य वस्तुओं की सप्लाई होती है। अब तेल और आटा कैल्शियम और आयरन युक्त होगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने सप्लाई शुरू करने से पहले इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से सलाह-मश्विरा किया है।

अगले महीने से प्रदेश के डिपो में पौष्टिक युक्त खाद्य वस्तुओं की सप्लाई शुरू होगी। हिमाचल में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। नीति आयोग ने पहले ही चावल में आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए और डी देने की बात कही है।

अब हिमाचल सरकार ने तेल और आटे में भी यह पौष्टिक तत्व मिलाने का फैसला लिया है। हिमाचल में साढ़े 12 लाख एपीएल परिवार हैं, जिन्हें डिपो में आटा मिलता है, जबकि साढ़े पांच लाख बीपीएल परिवार हैं, जिन्हें गेहूं दिया जा रहा है। तेल सभी उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि डिपो में मिलनी वाली खाद्य वस्तुओं में अगर कैल्शियम और आयरन मिलाया जाता है तो महिलाओं और बच्चों में खून की कमी दूर हो सकेगी।

हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को कैल्शियम और आयरन युक्त आटा और तेल देने का फैसला लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान से इस बारे में चर्चा हुई है। जल्द पौष्टिक तत्वों से युक्त आटा और तेल में उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षकों के हजारों पद न भरने पर कोर्ट की हिमाचल सरकार पर तल्ख टिप्पणी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल हाईकोर्ट ने भरी अदालत में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार शिक्षकों से जुड़े भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने जितना जटिल कार्य कर रही है।

प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद न भरने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तलख टिप्पणी की है। मामले पर सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने गत 26 जून को सरकार को आदेश दिए थे कि शिक्षकों से जुड़े आरएंडपी नियमों में आठ सप्ताह में संशोधन करे। इसके बाद संशोधित नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती की जाए। नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार ने इस बार फिर से तीन महीने की मांग की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह स्कूलों में खाली पड़े पदों को इसी शैक्षणिक सत्र में भरे।

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जेबीटी, एलटी, शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के कुल 4491 पद 31 जुलाई, 2019 तक खाली थे। 736 पद 31 जुलाई 2019 तक रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से खाली हुए।

3132 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। 2095 पदों को भरने के लिए पहले ही जरूरी स्वीकृति ले ली गई है। गौरतलब है कि शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र देकर अदालत को बताया था कि हिमाचल में शिक्षकों के 14,354 पद खाली हैं।

इनमें से प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली चल रहे हैं। इसी तरह अपर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद खाली हैं।

औद्योगिक ढांचा बनाने पर प्रदेश सरकार निवेशकों को देगी रियायतें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और औद्योगिक ढांचा बनाने के लिए सरकार निवेशकों को रियायतें और प्रोत्साहन देगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में सरकार निवेशकों के लिए साझा औद्योगिक और सोशल ढांचा तैयार करने और इन्हें अपग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेशक औद्योगिक पार्कों को विकसित करना चाहते हैं तो इन्हें निजी क्षेत्र में स्वयं चिह्नित या खरीदी भूमि में विकसित करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा आवंटित जमीन में भी ये पार्क तैयार किए जा सकते हैं।

इसके लिए निवेशक कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी ले सकेंगे। औद्योगिक पार्क विकसित करने को ए, बी और सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में यह उपदान कुल खर्च राशि का 25, 40 और 50 फीसदी तक दिया जाएगा। यह ए, बी और सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 15 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़ तक की सीमा रहेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

भारत ने चार यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इस पुरस्कार की घोषणा मलेशिया में आयोजित एक समारोह में की गई थी। इस पुरस्कार हेतु भारत के जिन चार स्थानों का चयनित किया गया है, उनमें अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान का विक्रम साराभाई पुस्तकालय शामिल है।

विश्व धरोहर वह स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक तथा पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत अहम होते हैं।

विश्व खाद्य दिवस 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भुखमरी की चुनौतियों के बारे में जनता में जागरूकता प्रसारित करने के साथ-साथ लोगों को भूख के विरुद्ध संघर्षमय कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना हैं। भारत में, दुनिया के करीब 23 प्रतिशत भूखे लोग रहते हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना साल 1945 में की गयी थी। यह दिवस सबसे पहले 16 अक्टूबर 1981 को आयोजित किया गया था।

फरवरी 2020 तक एटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम रहने को लेकर फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखने का फैसला किया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने हेतु अतिरिक्त सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।

पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में रखा गया था। ग्रे सूची में डालने के बाद देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है तथा अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है। पाकिस्तान आतंकवाद को आर्थिक सहायता देने के कारण से वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल रह चुका है।

एफएटीएफ ने श्रीलंका को ग्रे सूची से किया बाहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आंतकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन एफएटीएफ ने इस सूची से श्रीलंका को बाहर कर दिया है। कोलंबो गजट ने 19 अक्टूबर 2019 को अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया और कहा कि श्रीलंका अब एफएटीएफ की निगरानी के अधीन नहीं होगा। एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी संस्था है। यह संस्था वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले की लगातार 40वें दिन सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई शुरू होते ही साफ कर दिया था कि आज शाम को पांच बजे मामले में अंतिम सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 06 अगस्त 2019 से लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल रहे।

भारत में पशुधन की आबादी 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा जारी 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पशुधन की आबादी सात वर्षों में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

इस बार टैबलेट की सहायता से पशुगणना हुई है। भारत में बीते पांच सालों में गायों की संख्या 18 प्रतिशत बढ़कर 14.51 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में भैंसों की संख्या इस दौरान मात्र एक प्रतिशत बढ़ी है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बकरियों की संख्या दस फीसदी बढ़कर 14.9 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुअर की संख्या बारह फीसदी घटकर 90.6 लाख है। कुक्कुट की संख्या साल 2019 में लगभग सत्रह प्रतिशत बढ़कर 85 करोड़ 18.1 लाख हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ब्रिजिटल नेशन' पुस्तक का किया विमोचन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

'ब्रिजिटल नेशन' एन चंद्रशेखरन तथा रूपा पुरुषोत्तम द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लेखकों को एक दूरदर्शी पुस्तक लिखने हेतु सराहना की। पीएम ने कहा कि पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब प्रौद्योगिकी सकारात्मक रूप से लाखों भारतीयों के जीवन को बदल रही है। यह पुस्तक भविष्य का एक बहुत ही शक्तिशाली विजन प्रस्तुत करती है जहां प्रौद्योगिकी तथा मानव परस्पर लाभकारी पारिस्थितिकी तंत्र में सह-अस्तित्व में हैं। पीएम मोदी ने बताया कि प्रौद्योगिकी सुधार, परिवर्तन तथा प्रदर्शन हेतु किस प्रकार सरकारी योजनाओं का एक प्रमुख घटक रही है।

न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत में भिन्न-भिन्न परमाणु संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। पहले, परमाणु संयंत्रों को सिर्फ दक्षिणी भारत में स्थापित किया जाता था, लेकिन अब हरियाणा के गोरखपुर में एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

इंडिया एनर्जी फोरम की स्थापना साल 2001 में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समझने और उसे विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे मौजूदा समय में भारत के सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के प्रवक्ता का विशेष दर्जा प्राप्त हो चुका है। सम्मेलन के समय इस पर भी प्रकाश डाला गया कि देश में लाइट वाटर रिएक्टर तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी लगाये गये हैं।

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का लक्ष्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को समाप्त करना है। यह दिवस गरीबी में रहने वाले लोगों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर विशेष जोर देता है।

भारत में गरीबी का सबसे मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढ़िवादी सोच, अमीर गरीब में ऊंच-नीच का भाव, नौकरी की कमी, अशिक्षा में बढ़ोतरी, बीमारी इत्यादि है. भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1987 में फ्रांस में मनाया गया था।

महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित लगभग 27.9 प्रतिशत मामले पति या उसके परिजनों की

क्रूरता के खिलाफ दर्ज किये गये थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान हत्या के मामलों में 3.6 प्रतिशत की कमी आई है। जबकि अपहरण के मामले 9 प्रतिशत बढ़ गये है। साल 2016 में भारत में 1,06,958 केस दर्ज हुए जो साल 2017 में लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर 1,29,032 हो गये। इस मामले में, यूपी पहले स्थान पर है, जहां ऐसे मामले साल 2016 की अपेक्षा 19 प्रतिशत ज्यादा दर्ज हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, साल 2017 में हत्या के कुल 28,653 मामले सामने आये है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग एशियाई देशों में सबसे खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2019 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 102वें स्थान पर है। इस साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करने के लिए साल 2014 से साल 2018 के आंकड़ों का उपयोग हुआ है।

इस रिपोर्ट में भारत ब्रिक्स देशों में भी सबसे नीचे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान 94वें स्थान पर, बांग्लादेश 88वें स्थान पर, नेपाल 73वें स्थान पर तथा श्रीलंका 66वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6 से 23 महीने की उम्र के सभी बच्चों में से मात्र 9.6 प्रतिशत को न्यूनतम जरूरी आहार दिया जाता है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को मंजूरी दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला सेना में महिलाओं की बराबर की भागीदारी, लैंगिक समानता तथा केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिहाज से लिया है। रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में महिला कर्मियों की नियुक्ति एवं आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को बढ़ाने के आदेश दिये जिससे की सैनिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन का काम शुरू किया जा सके।

सैनिक स्कूलों के स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को उचित शिक्षण देकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश कराना था। साल 1961 में भारत के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। यह फैसला रक्षा मंत्रालय द्वारा 02 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल छिंगछिप में शुरू किए गये पायलट परियोजना की सफलता के बाद लिया गया है।

पहली बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन शुरू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआरसीटीसी के अनुसार, यह ट्रेन महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों को कवर करेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर यात्रा शुरू करेगी तथा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों की यात्रा करवाने के बाद सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। आईआरसीटीसी ने यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय मानक अनुभव देने हेतु बौद्ध सर्किट ट्रेन में कई व्यवस्थाएं की हैं।

इस ट्रेन की यात्रा आठ दिन और सात रातों की होगी। इस ट्रेन के टूर पैकेज में रेल यात्रा के साथ लग्जरी होटल में ठहराना, परिवहन, एयर कंडीशन बसों में सभी जगहों पर घुमाना तथा विभिन्न भाषाओं के टूर गाइड्स की व्यवस्था होगी। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को किराये से छूट दी गई है। 05 साल से 12 साल तक के बच्चों से पचास प्रतिशत किराया लिया जायेगा।

दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी– असम सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी। कैबिनेट की बैठक में नई 'भूमि' नीति को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि तथा एक मकान बनाने हेतु आधा बीघा जमीन मिलेगी।

नई नीति के अनुसार, असम में किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या दो से अधिक है, तो वे सरकारी योजनाओं जैसे ट्रैक्टर ऋण, आवास मुहैया कराने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होने वाले पंचायत, स्वायत्त परिषद और नगक निकाय चुनावों हेतु उम्मीदवारी पेश करने के भी योग्य नहीं होंगे।

केंद्र सरकार ने नई सुविधाओं के साथ पेश किया भीम 2.0 ऐप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप हब पोर्टल तथा इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री भी शुरू की। एनपीसीआई द्वारा विकसित यूपीआई आधारित एक भुगतान मंच है। यह दिसंबर 2016 में स्थापित किया गया था। इस ऐप के जरिये वास्तविक समय में कोष का हस्तांतरण होता है। भीम ऐप को और अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु इसमें नई चीजें जोड़ी गयी हैं।

पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक सेवा बंद की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

21 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक मेल सेवा को बंद कर दिया है। हालांकि, यह फैसला पाकिस्तान ने भारत को बिना नोटिस दिये किया है।

पाकिस्तान ने 27 अगस्त 2019 को भारतीय डाक अधिकारियों से अपने देश हेतु डाक मेल की एक खेप को स्वीकार किया था, यह सेवा उसके बाद से बंद है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कैलिफोर्निया में भीषण आग, अंधेरे में डूबे 2 लाख परिवार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कैलिफोर्निया के जंगलों में बीते सप्ताह आग के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2 लाख परिवारों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 50 से अधिक इंजन, आठ एयर टैंकर और तीन बुलडोजर द्वारा समर्थित 500 से अधिक अग्निशामकों को इस आग को बुझाने के लिए तैनात किया गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आग की लपटे अब किनारे बसे रिहाइशी इलाकों में पहुंचने लगी है। इसके

बाद से अफरातफरी मची हुई है। यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।

इस भंयकर आग लगने के बाद स्थानीय निवासियों को आस-पास के स्थान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। आग की लपटें 20 मिनट में 200 एकड़ तक फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक, इस आग से काफी नुकसान हो गया। इसके साथ ही कई बिल्डिंग भी बाहर से जल गई।

इससे पहले 12 अक्टूबर को दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया था। इस आग के चलते यहां से 1, 00,000 लोगों को वहां से निकलना पड़ा था। इस आग के लपटें से कई दर्जन घर नष्ट हो गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि इस आग को बुझाने में कई दिन लग सकते हैं।

इससे पहले 19 नवंबर 2018 को उतरी कैलिफोर्निया के जंगलों में भयंकर आग लगी थी। इस आग में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई थी।

सबसे बड़ी गैलेक्सी का लगा पता, हल हो सकती है ब्रह्मांड की पहेलियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो

खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी आकाशगंगा का पता लगाया है, जो ब्रह्मांडीय धूल के बादलों के बीच छुपी हुई है और माना जा रहा है कि यह आकाशगंगा शुरुआती ब्रह्मांड से भी पुरानी है। खगोलविदों का दावा है कि यह अब तक खोजी गईं सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यह खोज नई आकाशगंगाओं का पता लगाने लिए खगोल विज्ञानियों को प्रोत्साहित कर सकती है।

अमेरिका की मैसाच्युसेट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'यह खोज हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी आकाशगंगाओं के शुरुआती दौर के बारे में नई जानकारियां देती है। साथ ही इनके बारे में एक नया नजरिया पेश करती है।' ऑस्ट्रेलिया की स्वाइनबर्न प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक इवो लाबे ने कहा, 'यह एक विशालकाय आकाशगंगा है, जिसमें लगभग उतने ही तारे

हैं जितने हमारे मिल्की वे में है, लेकिन इसमें एक फर्क यह है कि इस आकाशगंगा के तारों की गतिशीलता हमारे मिल्की वे से सौ गुना ज्यादा है।' एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, या अल्मा का उपयोग किया। अल्मा 66 रेडियो दूरबीनों का एक संग्रह है, जो चिली के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है।

इस अध्ययन की मुख्य लेखिका क्रिस्टीना विलियम्स ने कहा, यह बहुत रहस्यमय आकाशगंगा है। इसका प्रकाश अन्य आकाशगंगाओं से बिल्कुल अलग है। जब मैंने देखा कि यह आकाशगंगा किसी अन्य तरंग दैर्ध्य में दिखाई नहीं देती, तो इसके प्रति हमारा उत्साह और बढ़ गया, क्योंकि इसका मतलब है कि संभवतः यह आकाशगंगा अंतरिक्ष में बहुत दूर धूल के बादलों के बीच छिपी हुई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसका सिग्नल इतनी दूर से आया था कि पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.25 करोड़ लग गए। खगोलविदों का मानना है कि यह खोज खगोल विज्ञान में लंबे समय से चली आ रही पहेलियों को हल कर सकती है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से कुछ बड़ी गैलेक्सी कैसे दिखाई देती हैं और सैद्धांतिक रूप से यह बहुत जल्दी कैसे परिपक्व हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पता लग सकता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखी जाने वाली छोटी आकाशगंगाएं तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है।

सोशल मीडिया पर लैबनान में लगा बैन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्मार्ट मोबाइल फोन लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद अहम है। लेबनान में व्हाट्स ऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर टैक्स लगाए जाने से पूरे शहर में लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसकी वजह से पूरा लेबनान पिछले कई दिनों से जल रहा है। गुस्से का आलम ये है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध वापस लेने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है।

लेबनान सरकार ने बीते

अक्टूबर को व्हाट्स ऐप और फेसबुक मैसेंजर जैसे कुछ सोशल मीडिया ऐप पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत

सोशल मीडिया ऐप के जरिए फोन कॉल करने पर टैक्स लागू किया गया था। सरकार ने ऐप बेस्ट कॉलिंग पर प्रतिदिन 0.20 डॉलर (भारतीय मुद्रा में 14.16 रुपये) का टैक्स लगा दिया था। सरकार की इस घोषणा के थोड़ी देर बाद ही लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं थी। इसके थोड़ी देर बाद ही लेबनान ने अपने फैसले को वापस ले लिया था।

इसलिए सरकार ने लगाया था टैक्स

लेबनान सरकार ने ये फैसला देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए लिया था, जो जनता को रास नहीं आया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी।

गुस्साए लोगों ने पूरे शहर का ट्रैफिक जाम कर दिया। सड़कों पर टायर और फर्नीचर जलाने लगे। कई जगहों पर लोगों की सुरक्षाबलों से सीधी झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों को बल प्रयोग और आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा था। इन झड़पों में काफी संख्या में लोग घायल हुए थे।

हिंसा के अगले दिन लेबनान के प्रधानमंत्री साद अल-हीरो ने कहा था कि देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है।

ऐसे में लोगों को संयम बरतना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था।

6.6 करोड़ साल पहले हुई थी सामूहिक विनाश की घटना, महासागर भी हुए थे प्रभावित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शोधकर्ताओं ने कहा कि सामूहिक विनाश की घटना में कैल्सीफायर भी प्रभावित हुए थे। सामान्यत इन जीवों पर अम्ल का ज्यादा असर नहीं देखा जाता। 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी में उल्कापिंडों के गिरने से हुई सामूहिक विनाश की घटना में कई जीव-जंतुओं का समूल नाश हो गया था। इस दौरान पृथ्वी के वातावरण में सल्फर की मात्रा बढ़ गई थी, जिससे यहां के महासागर और ज्यादा अम्लीय हो गए थे। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'लाखों साल पहले अंतरिक्ष से अत्यधिक मात्रा में उल्कापिंड़ों के गिरने से पृथ्वी के लगभग तीन चौथाई जीव-जंतु और वनस्पतियां विलुप्त हो गई थीं। साथ ही इन उल्कापिंडों से निकली सल्फर गैस पूरे वातावरण में फैल गई थी।

चीन की एक और चाल, नेपाल सेना को 148 करोड़ देगा ड्रैगन, भारत को घेरने में जुटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीते कुछ साल से चीन लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में उसने एक और कदम बढ़ाया है। अब वह आपदा राहत सामग्री के नाम पर अगले तीन साल में नेपाल सेना को 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 148 करोड़ रुपये) की मदद देगा। नेपाल सरकार ने हाल ही में इसकी जानकारी दी।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारी संता बहादुर ने कहा कि अगले तीन साल तक सेना की जरूरत के हिसाब से उन्हें चीन की मदद पहुंचाई जाएगी।

बता दें कि नेपाल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन ने यहां बड़ा भारी निवेश किया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ी है। बीते 12 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नेपाल की यात्रा पर आए थे। पिछले दो दशक में चीन के किसी राष्ट्रपति की नेपाल में यह पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों पक्ष में कई करार भी हुए।

बता दें कि कल चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा था कि चीन के साथ ताइवान के एकीकरण की प्रक्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता है। ज्ञात हो कि गृहयुद्ध के बाद 1949 में अलग हुए ताइवान को चीन अपना क्षेत्र मानता है।

करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर भारत-पाक का हस्ताक्षर अब बगैर वीजा जा सकेंगे करतारपुर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत-पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल के नेतृत्व में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल करतारपुर जीरो लाइन पर मौजूद था। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने इस कॉरिडोर से संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया।

हस्ताक्षर के बाद विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने कहा, हमारी ओर से हाइवे व पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग समेत तमाम आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है ताकि समय से कॉरिडोर का काम पूरा हो सके।

उन्होंने कहा श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल आज से लाइव हो जाएगा। यह पोर्टल है- http://prakashpurb550.mha.gov.in'

उन्होंने कहा, सुबह से शाम तक यह कॉरिडोर खुला रहेगा।

सुबह जाने वाले श्रद्धालुओं को उसी दिन शाम को लौटना होगा। पूरे साल कॉरिडोर खुला रहेगा और यदि किसी कारण इसे बंद किया जाएगा तो इसकी सूचना एडवांस में दे दी जाएगी।

उन्होंने बताया, सभी समुदाय के भारतीय श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए वीजा फ्री होगा। श्रद्धालुओं को केवल अपना वैध पासपोर्ट ले जाना होगा।

चीन ने एक चौथाई विदेशी मीडिया वेबसाइटों पर लगाया प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने देश में काम करने वाले विदेशी समाचार संगठनों के एक वर्ग पर रोक लगा दी है। इसके बाद वहां के नागरिक इन संस्थानों की वेबसाइटों की खबरें देख और पढ़ नहीं सकेंगे। प्रतिबंधित वेबसाइटों में बीबीसी, ब्लूमबर्ग, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और योमीयूरी सिम्बन आदि शामिल हैं। प्रेस पर निगरानी रखने वाली संस्था फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ चाइना (एफसीसीसी) ने एक बयान में कहा, दरअसल चीन के नागरिक अब 215 अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों में से 23 फीसद का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इन समाचार संगठनों के पत्रकार चीन में काम करते हैं।

एफसीसीसी ने बताया कि मुख्य रूप से अंग्रेजी में काम करने वाले 31 फीसद समाचार संगठनों पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग चीन में नहीं खुला था। तब भी लोगों को लगा था कि कहीं यह नई विदेशी वेबसाइट ना हो जिस पर चीन के सेंसर ने प्रतिबंध लगा दिया हो। चीन में बिंग सर्च इंजन के यूआरएल 'सीएन डॉट बिंग डॉट कॉम' को खोलने पर गलत पता (एरर) का संदेश दिख रहा था।

माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने उस समय कहा था कि हम पुष्टि करते हैं कि मौजूदा समय में बिंग को चीन में नहीं खोला जा सकता है। हम आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि कंपनी इस मामले की जांच कर रही है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था में ऑनलाइन सेंसरशिप भी लगायी जाती है। इसे प्रौद्योगिकी जगत में ग्रेट फायरवाल के तौर पर जाना जाता है। गौरतलब है कि चीन में पहले से ही गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी साइट्स पर बैन लगा हुआ है। यहां तक कि चीन के लोग माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीन में सर्च इंजन के लिए लोग बायडू और सोशल मीडिया साइट्स के तौर पर वीबो का इस्तेमाल करते हैं।

भारतीयों को ब्राजील जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी-राष्ट्रपति बोल्सोनारो

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कहा कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ने चीनी और भारतीय पर्यटक या व्यवसायी लोगों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में आवश्यकता को कम किया है। बोल्सोनारो साल की शुरुआत में सत्ता में आए थे और उन्होंने कई विकसित देशों से वीजा आवश्यकताओं को कम करने की नीति बनाई थी, लेकिन, हाल में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान की गई घोषणा, वह पहली है जिसमें उन्होंने विकासशील देशों के लिए भी उस नीति का विस्तार किया है।

इस साल की शुरुआत में, ब्राजील सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों और व्यापारियों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। हालांकि, उन देशों ने ब्राजील के नागरिकों के लिए अपनी वीजा आवश्यकताओं को नहीं।

वोटरों को गिफ्ट देने पर डोनेशन स्कैंडल में फंसे जापान के व्यापार मंत्री, देना पड़ा इस्तीफा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जापान के व्यापार मंत्री ने डोनेशन कांड में नाम आने पर इस्तीफा दिया। जापान के नए व्यापार मंत्री ने वोटरों को धन और उपहार देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी जानकारी दी। एक मैगजीन ने बताया कि जापान के व्यापार मंत्री ईशू सुगावरा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक परिवार को 20,000 येन (जापानी मुद्रा) दिया। जिसके बाद वह संदेह के घेरे में आ गए। क्योडो समाचार एजेंसी ने कहा कि उन्होंने अन्य मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार दिए, जिसमें महंगे तरबूज, यहां तक कि केकड़े भी शामिल हैं। इसमें शामिल रकम जापान के चुनाव कानून का उल्लंघन है। इसलिए उनपर कार्रवाई हुई है।

जापान के प्रधानमंत्री ने बताया कि मंत्री सुगावरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।सुगावारा ने आबे को बताया और बाद में संवाददाताओं से कहा यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि संसदीय बहस का यह मुद्दा स्टाल (घोटाले के कारण) बने। सुगावारा को हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को संभालने के प्रमुख पोर्टफोलियो को नहीं संभाला।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

THE CURRENT AFFAIRS 2019

- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस स्कूल में 2021–22 सत्र से लड़कियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है – सैनिक स्कूल
- भारत और जिस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य-अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज-5 का आयोजन किया जा रहा है – ओमान
- वह राज्य सरकार जिसका संस्कृति विभाग विश्व प्रसिद्ध 'खोन रामलीला' के लिए देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है – उत्तर प्रदेश
- वह देश जो 91वीं इंटरपोल महासभा का साल 2022 में आयोजन करेगा – भारत
- IRCTC द्वारा आरंभ की गई विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन जितने दिन में भारत और नेपाल में स्थित बौद्ध स्थानों की यात्रा करायेगी – आठ
- भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज श्रृंखला के अंतिम मैच में जिस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला है – शाहबाज नदीम
- अंतरिक्ष के इतिहास में जितनी महिलाओं ने पहली बार बिना किसी पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया – दो
- यूनिसेफ के मुताबिक, 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के सर्वाधिक मामले जिस देश में दर्ज हुए है – भारत
- नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2019 में यह राज्य पहले स्थान पर है – कर्नाटक
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है – दिल्ली
- यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट The State of the World's Children के अनुसार भारत में औसत भार से कम बच्चों का प्रतिशत – 33 प्रतिशत
- वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6,1 और 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है – IMF
- वह पर्यावरणविद जिसे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है – चंडी प्रसाद भट्ट
- भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का लेटेस्ट संस्करण है – 10वां
- चीन और नेपाल के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के बाद किये गये समझौतों की संख्या – 20
- वह आईपीएल टीम जो सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी –आरसीबी
- वह राज्य जो निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य बना है – केरल
- वह राज्य जहां शिरुई लिली उत्सव 2019 आयोजित किया जा रहा है – मणिपुर
- भारत और जिस देश की वायुसेना के बीच हवाई युद्ध अभ्यास 'शिन्यु मैत्री' का आयोजन किया जा रहा है – जापान
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को जो स्थान मिला है – 102
- जिस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है – 16 अक्टूबर
- जिसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है – मार्गरेट एटवुड
- जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर क्षेत्र में फोन सुविधा को बेहतर बनाये जाने के लिए प्रत्येक जिले में जितने पीसीओ बनाने की घोषणा की है – 50
- मुंबई के जिस ओपनर ने 50–ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं – यशस्वी जयसवाल
- मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं – 100 मैच
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने साल 2019–20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है – 6.1 प्रतिशत
- यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार हेतु मुंबई के 155 साल पुराने फ्लोरा फाउंटेन और दो अन्य विरासत स्थल सहित कुल जितने स्थानों को भारत से चयनित किया गया है – चार
- अमेरिका और जिस देश के बीच करीब 15 महीने से जारी ट्रेड वॉर से दुनिया को कुछ राहत मिलती दिख रही है – चीन
- जिस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है – अभिजीत बनर्जी
- जिसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है – कैस सैय्यद
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन जिस राज्य में किया गया है – मध्य प्रदेश
- भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन-2019' का आयोजन मिजोरम में किया जायेगा – जापान
- विश्व मानक दिवस-2019 जिस दिन मनाया गया – 14 अक्टूबर
- भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया – नई दिल्ली
- आरबीआई ने मुंबई स्थित पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खातों की निकासी सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर जितने हजार रुपये कर दी है – 40,000 रुपये
- अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 15 अक्टूबर
- आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाए जिस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है – सुपर ओवर
- विश्व बैंक ने जिस दक्षिण एशियाई देश की जीडीपी वृद्धि दर 2019 में 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है – बांग्लादेश
- वह देश जिसकी ऊर्जा कम्पनी 'टोटल' ने 'अडाणी गैस' की 37.4 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है – फ्रांस
- जिस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किये जाने वाले वैश्विक नेता बन गये हैं – इंस्टाग्राम
- भारतीय नन जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा 'संत' की उपाधि से सम्मानित किया गया हैइ – मरियम थ्रेसिया
- जिस देश के रहने वाले जोसेफ एंटनी फर्डीनेंड के 218वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें एक डूडल समर्पित किया है – बेल्जियम
- हाल ही में जिस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है – लक्ष्य सेन
- अमेरिका ने तेल संयत्रों पर ड्रोन हमलों के कारण खतरे की बढ़ती आशंका के मद्देनजर जिस देश में 3,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने की घोषणा की है – सऊदी अरब
- भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चौंपियनशिप्स के 48-किलोग्राम भारवर्ग में जो पदक जीता है – रजत पदक
- विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है – 6 प्रतिशत
- मृत्युदंड विरोधी दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 10 अक्टूबर
- हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में जिस राज्य के चाय बागानों में हो रहे श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है – असम
- बेल्जियम के जिस शहर में यूरोपीय नेताओं की बैठक से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के वार्ताकारों के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति बन गई है – ब्रसेल्स
- जिस राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉ. वाई.एस.आर. नवोदयम योजना लॉन्च की – आंध्र प्रदेश
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 50वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच जिस राज्य में आयोजित किया जायेगा – गोवा
- भारत और फिलीपींस ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनीला यात्रा के दौरान जितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये – चार
- इंडिया एनर्जी फोरम ने जिस शहर में न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव-2019 (एनईसी) का आयोजन किया – नई दिल्ली
- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में जिस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया है – रोहित शर्मा
- विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन-स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे और 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के जिस शहर में पहुंची – सिडनी
- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के जिस क्रिकेटर ने टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली दो गेंदों में दो छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गये – उमेश यादव
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये जिस भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं – ऑन टैप
- हाल ही में जिस राज्य में 'शिरुई लिली' महोत्सव आयोजित किया गया – मणिपुर
- वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'भारत की लक्ष्मी' अभियान का समर्थन किया है – पीवी सिंधु
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है – 6.1
- हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं – उत्तर प्रदेश
- भारत में जिस तारीख को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है – 21 अक्टूबर
- हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा – असम
- जिस स्थान पर इतिहासकारों ने 2,000 वर्ष से अधिक पुरानी एक सड़क की खोज की है – येरुशलम
- भारत ने रांची में हुए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और जितने रनों से हराकर सीरीज में 3–0 से जीत हासिल की – 202
- वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है – पाकिस्तान
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर ने हाल ही में जिस पेमेंट एप का नया संस्करण जारी किया है – भीम 2.0

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- राष्ट्रीय कृषि एं ग्रामीण विकास बैंक ने सौर सिंचाई योजना के लिए हिमचल प्रदेश को कितने करोड़ का बजट दिया है – 75 करोड़
- हिमाचल हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया है – वी रामासुब्रमनियन
- किस जिले से हाल ही में पोषण अभियान की शुरूआत की गई – सिरमौर
- शशि जिन्होंने भारतीय टीम में एशियन पैरा कब्बड्डी मैच में गोल्ड मैडल जीता, उनका संबंध हिमाचल के किस जिले से है – मंडी-करसोग
- हिमाचल सरकार ने सिरमौर जिले के पच्छाद में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरूआत की है – 42.32 करोड़
- हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बस शुरूआत की जाएगी – 8
- हिमाचल प्रदेश के किस विभाग को हाल ही में दिल्ली में द स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गसा – शिक्षा विभाग
- किस दर्रे को जल्द ही रोप वे से जोड़ा जाएगा – रोहतांग दर्रा-3,978 मीटर
- हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल को देश भर में स्वच्छता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है – बिलासपुर के नंदग्राम स्कूल को
- प्रदेश में एकलव्य स्कूलों का निर्माण करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी – 392 करोड़
- हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार ने कौन से डेमोक्रेसी डे धर्मशाला में मनाया – 59वां. पहली बार 2 सितंबर 1960 को मनाया गया था
- हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जल्द ही नेशनल बाक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा – शिमला
- प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विश्व बैंक कितने करोड़ देगा – 500 करोड़

आर्थिक सर्वेक्षण

- हिमाचल में किस प्रमुख बागवानी फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई – सेब
- चंबा से कौन सा कल्सटर रूर्बन मिशन के तहत शामिल किया गया है – सिंहुता
- हिमाचल में ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है – 11 हजार प्रतिवर्ष
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हिमाचल के कौन से जिले शामिल किए गए हैं – हमीरपुर और कांगड़ा
- हिमाचल में चाय की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल कितना है – 2310 हैक्टेयर
- हिमाचल में कहां पर लेबर कोर्ट कम – इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित किए हैं – शिमला और धर्मशाला
- हिमाचल की कुल पनबिजली क्षमता क्या है – 27,436
- फ्रूट क्राप्स के तहत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है – 49 प्रतिशत
- विश्व महिला उत्थान योजना में शामिल किए गए 100 जिलों में हिमाचल के किस जिलों को शामिल किया गया है – ऊना
- बगवानी के संवर्धन के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर के तहत किस स्थान पर स्थापित की गई है – पालमपुर
- कृषि उपज के विपणन के लिए किस स्थान पर एक आधुनिक बाजार परिसर कार्यात्मक रहा – सोलन
- किन स्थानों पर सीए स्टोर खोले गए – गुम्मा और जलोड़ टिक्कर
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक कौन सा है – यूको बैंक
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं – 40 हजार

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

युवा आजीविका योजना

युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। अगर कोई युवा अपना व्यवसाय शुरु करना चाहता है तो उसे आर्थिक सहायता से लेकर कौशल प्रशिक्षण तक की व्यवस्था है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब उद्यमी के तौर पर व्यवसाय तो व्यक्ति शुरु कर देता है लेकिन सही मार्गदर्शन और व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए तकनीकी सहायता उसे नहीं मिल पाती। यही कारण है कि छोटे उद्यमी अक्सर व्यवसाय शुरु करने के एक साल के भीतर ही हिम्मत हार जाते हैं और कोई जोखिम उठा कर व्यवसाय को आगे ले जाने की जगह उसे बंद करना ही बेहतर समझते हैं। इसी समस्या से पार पाने के लिए मिशन रीव की ओर से विकास मॉडल के तहत बनाए गए दस प्रभागों में उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास प्रभाग को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। द रीव टाईम इस अंक में हम आपको बता रहे है कि सरकार की युवा योजना क्या है और मिशन रीव इसमें कैसे आपकी मदद कर सकता है।

अगर आप भी अपना काम करना चाहते हैं और पूंजी की दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार की युवा आजीविका योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए हिमाचल सरकार ने युवा आजीविका योजना शुरू की है। युवा आजीविका योजना नाम की इस स्कीम में सरकार बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी और उसके ब्याज पर पहले साल 8 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।

युवा आजीविका योजना में बेरोजगार युवक अपनी पसंद के किसी भी कारोबार के लिए सरकारी लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं। युवा आजीविका योजना जुलाई 2018 में ही शुरू की गयी है। युवा आजीविका योजना के तहत किसी युवा उद्यमी को 30 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर 8 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। दूसरे साल में ब्याज सब्सिडी छह फीसदी और तीसरे साल में चार फीसदी हो जाती है।

युवा आजीविका योजना के तहत प्रदेश के 18 से 40 साल के युवाओं को खुदरा व्यापार, दुकान, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म), परंपरागत शिल्प आदि कारोबार शुरू करने पर लोन मिलता है। योजना में लोन की रकम पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी (भूमि व मकान को छोड़कर) मिलती है। युवा आजीविका योजना में युवतियों व महिलाओं को लोन पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। अगर युवा आजीविका योजना के तहत कोई बेरोजगार युवा जमीन और भवन किराए पर लेता है तो उसकी प्रक्रिया में 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की जगह 3 प्रतिशत की दर से ही ड्यूटी ली जाती है।

इस साल के बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने योजना के लिए 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। सरकार का यह मानना है कि अगर कोई युवा इस योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करता है तो 30 लाख रुपये के निवेश से शुरू होने वाले काम में कम से कम 5–10 और युवाओं को काम मिलेगा। इससे प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में खासी मदद मिल सकती है। युवा आजीविका योजना के उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पहले से कई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। इनमें शिमला, कसौली, डलहौजी, धर्मशाला एवं कांगड़ा जैसी जगहें शामिल हैं।

राज्य सरकार चाहती है कि युवा पर्यटकों को सुविधा पहुंचाने और उसके जरिये कमाई करने के हिसाब से अपना कारोबार शुरू करें। इसे देखते हुए सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के लाभ हिमाचल के युवाओं को कारोबार के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। लोन की रकम पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी (भूमि व मकान को छोड़कर) मिलती है। बेरोजगार युवा कारोबार 'उद्यम' कामकाज के लिए राज्य सरकार से लोन ले सकते हैं।

युवा आजीविका योजना का लाभ उठाने की शर्त

युवा आजीविका योजना 18 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं के लिए है। आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो। आवेदक के पास आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं होना चाहिए। युवा आजीविका योजना में बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये के लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। युवा आजीविका योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। बेरोजगार युवा का बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। आवेदक के पास हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक एफिडेविट जिसमें आपके जॉब नहीं करने का जिक्र हो।

''मिशन रीव ने उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने और प्रशिक्षण से लेकर लोन सुविधा तक सराहनीय पहल की है। उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास यानि ईबीडी के अंतर्गत मिशन रीव उद्यमिता सहयोग सेवाएं यानि ईएसएस देने में प्रयासरत है जिसमें कई युवाओं को लोन व अन्य सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा यह प्रयास निरंतर जारी है।

युवाओं को बेरोजगार होने की स्थिति में अपना कोई भी व्यवसाय शुरु करने के लिए मिशन रीव से जुड़कर उसकी समस्त औपचारिकताओं से मुक्ति देकर रीव व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण एवं लोन आदि की सुविधा प्रदान कर व्यवसाय को स्थायित्व देने में सहयोग कर रहा है।''

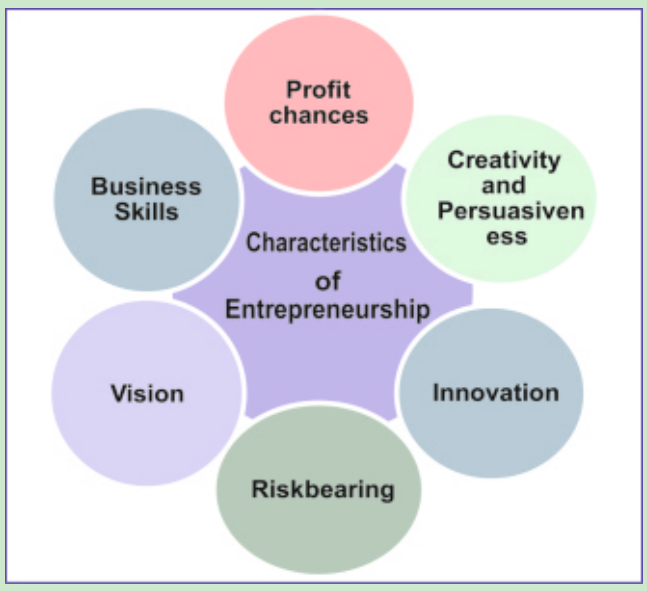

उद्यमिता के संदर्भ में मिशन रीव

मिशन रीव को सदस्यों की आवश्यतानुसार इस प्रभाग में नव उद्यमियों के लिए विशेष सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन करने का प्रावधान है। मिशन रीव कैसे नया व्यवसाय शुरू करने में अथवा पहले से स्थापित व्यवसाय को आगे ले जाने में आपकी सहायता करता है, इस प्रक्रिया को आप यहां समझ सकते हैं:

ऐसे सहयोग करता है मिशन रीव

- लघु उद्योग एवं व्यवसाय के लिए विश्लेषणात्मक वातावरण तैयार करना
- उत्पादों अथवा सेवा के चयन में सहयोग करना तथा उसके लिए प्रस्ताव तैयार करना
- लघु उद्योगों की स्थापना के लिए समस्त औपचारिकताओं और आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करना
- लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिए प्रबंधकीय कौशल की व्यवस्था करना

विशेष सेवाएं

- व्यवसाय योजना की पहचान करना
- वित्तीय एवं तकनीकि संस्थानों से संपर्क करवाना
- समस्त सरकारी लाईसेंस, स्वीकृति पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
- व्यवसायिक एवं वित्तिय योजना निर्माण
- तकनीकि सहयोग एवं प्रशिक्षण

आवश्यकता आकलन

- किसी भी व्यक्ति की सहायता करने से पूर्व मिशन रीव के तहत सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। इस आकलन के बाद आवश्यकता के अनुसार उद्यमी बनने वाले इच्छुक व्यक्ति की सहायता की जाती है।

बैंकिंग एवं वित्तीय खंड के अंतर्गत सेवाएं

- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सहयोग
- व्यवसाय स्थापन हेतु सहयोग
- वित्तीय सहयोग
- व्यवसाय योजना सहयोग
- व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सहयोग
- सूचना तकनीकी सहयोग

केसस्टडी

- विकास खण्ड जुब्बल - कोटखाई में **बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस प्रभाग** के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित कर रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय पहल की है। गौरव शर्मा जो कि जुब्बल से संबन्धित है, द्वारा मिशन रीव में आवश्यकता आकलन के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया गया।
- इसके लिए मिशन रीव ने समस्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर कार्य किया तथा फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित किया। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत १० लाख 40 हज़ार रुपये थी जिसके लिए मिशन रीव द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युको बैंक जुब्बल से लिंक करवाकर गौरव शर्मा को यह लोन स्वीकृत करवाया गया।
- लोन लेने के बाद मिशन रीव ने ही मशीन और उसके उपकरणों को पहचान कर स्थापन में भी सहयोग किया। इस प्रोजेक्ट को बनाने, लगाने तथा क्रियान्वयन में मिशन रीव ने संपूर्ण सहयोग किया। गौरव शर्मा ने द रीव टाइम्स को बताया कि मिशन रीव को आवश्यकता आकलन में रोजगार के लिए आवेदन किया था तथा इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को लगाने पर चर्चा के बाद उसके स्थापन के लिए मिशन रीव ने इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाया है।
- इस प्रोजेक्ट की पूरी रुपरेखा और क्रियान्वयन मिशन रीव के तहत हुआ तथा इसकी स्थापना के बाद न केवल मुझे अपने घर पर ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि मेरे साथ कई बेरोजगारों को भी रोजगार मिला है। मैं मिशन रीव का बहुत आभारी हूं क्योंकि मुझे इस मशीन और व्यवसाय की जानकारी नहीं थी।

केसस्टडी

- राजगढ़ सिरमौर से प्रीतम ठाकुर ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने मिशन रीव के तहत आवश्यकता आकलन में ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ के लिए आवेदन किया था।
- मिशन रीव ने इस आवश्यकता को समयसीमा के तहत ही पूरा करते हुए राजगढ़ में टीम के सहयोग से इसकी पूरी रुपरेखा तैयार कर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यह अनुमानित रुप से 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट था। संबन्धित बैंक से लिंक कर यह लोन स्वीकृत करवाया गया तथा उसके बाद ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ को स्थापित कर उद्यमिता के लिए बेहतर शुरुआत की गई। प्रीतम ठाकुर ने बताया कि मुझे ऑटामोबाइल में प्रशिक्षित होने के बाद भी रोजगार के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था। न ही मुझे औपचारिकताओं का पता था। ऐसे में मिशन रीव ने मेरा मार्गदर्शन किया तथा प्रोजेक्ट बनाकर, लोन स्वीकृत करवाकर स्थापित कर दिया। मेरे साथ इसमें कई और बेरोजगारों को मैं अब रोजगार दे रहा हूं। मिशन रीव को इसके लिए आभार जताया।

"मुख्यमंत्री युवा आजीविका" योजना शुरू

- योजना के अंतर्गत 30 लाख ₹ तक की राशि तक भूमि व मकान को छोड़कर किए गए निवेश पर मिलेगा 25% उपदान तथा महिला उद्यमियों को मिलेगा 30% उपदान
- 30 लाख ₹ तक के ऋण पर 3 वर्षों के लिए मिलेगा 3% ब्याज अनुदान
- हिमाचल सरकार ने योजना के लिए किया है 75 करोड़ ₹ बजट का प्रावधान

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कृषोन्नति योजना हरित क्रांति

किसानों के विकास के लिये शुरु की गई महत्वकांक्षी योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो :
सरकार ने देश में चल रही 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' की समय सीमा तय की है और अब ये योजना साल 2020 तक हमारे देश में जारी रहेगी। छतरी योजना यानी 'अम्ब्रेला स्कीम' 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के अंदर ग्यारह योजनाओं को शामिल किया गया है और ये सभी योजनाएं हमारे देश के किसानों के विकास और उनकी इनकम में वृद्धि से जुड़ी हुई हैं।

ऐसे समझें

योजना का नाम : छतरी योजना 'हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना'
किसके द्वारा चलाई गई ये योजना : केन्द्र सरकार
योजना के अंतर्गत आने वाली कुल योजनाएं : 11
योजना की अवधि : साल 2020 तक
कृषि क्षेत्र से जुड़ी है ये योजना :
कृषि क्षेत्र योजना का बजट : 33,26 9.9 76 करोड़
छतरी योजना 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के लक्ष्य छतरी योजना - 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' की मदद से सरकार किसानों की हर संभव मदद करना चाहती है ताकि किसान फसलों का उत्पादन अच्छे से कर सकें और इनकी इनकम में बढ़ोतरी हो सके।
इन योजना की मदद से सरकार कृषि क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने चाहती है। ये सभी योजनाएं (11 योजनाएं) कृषि क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं जैसे कि कपास की खेती में होने वाली परेशानी और पौधों में कीड़े लगने सहित अन्य समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि किसानों की समस्याओं के हल होने से उनकी फसलों का उत्पादन और बढ़ सकेगा, जिससे की किसानों को बेहतर लाभ मिलना सुनिश्चत हो सकेगा।

छतरी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी 11 योजनाओं की जानकारी

नीचे बताई गई सभी योजनाओं को पहले सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जा रहा था लेकिन साल 2017–18 में, इन सभी योजनाओं को क्लब करने का फैसला लिया गया जिसके बाद से ये सब योजनाएं छतरी योजना - 'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' के तहत जानी जाती है।

1.बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन

योजना का लक्ष्य - बागवानी क्षेत्र से जुड़ी इस योजना का लक्ष्य इस क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ बागबानी उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों को बागबानी क्षेत्र से जोड़ना है और उनको आय समर्थन देना है ।
योजना का बजट- कुल 33,26 9.9 76 करोड़ रुपए के बजट में से सरकार इस योजना पर 7533.04 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

2.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तेल बीज और तेल पाम राष्ट्रीय मिशन (एनएमओयूपी)

योजना का लक्ष्य
इस योजना की मदद से सरकार हमारे देश में चावल, गेहूं, दाल, अनाज और अन्य तरह की फसलों के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और अपना ये लक्ष्य सरकार उपयुक्त तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से करेगी। इसके अलावा सरकार इस योजना की मदद से देश में तेल के बीजों की खेती में वृद्धि करना चाहती है ताकि हमारे देश को अन्य देशों से तेल का आयात नहीं करवाना पड़े।
योजना का बजट - इस योजना को सही तरह से चलाने के लिए सरकार ने 6893.38 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए निर्धारित किया है।

3. स्थिर कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)

योजना का लक्ष्य
स्थिर कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य उपयुक्त मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ कृषि तकनीक की मदद से स्थिर कृषि को हमारे देश में बढ़ावा देना है। योजना का बजट - इस योजना के लिए सरकार 33,269.976 करोड़ रुपए में से 3980.82 करोड़ रुपये आवंटित करेंगी ।

4. कृषि विस्तार के लिए उप मिशन (एसएमएई)

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करना, किसानों का सामाजिक - आर्थिक सशक्तिकरण करना, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की व्यवस्था को और मजबूत करना, स्टेकहोल्डर्स के बीच संपर्क कायम करना, मानव संसाधन विकास को समर्थन देना और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आईसीटी उपकरण को इनहृवेटिव बनाना है।
योजना का बजट - इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार को 2961.26 करोड़ रुपए का खर्चा आऐगा ।

5. बीज और रोपण सामग्री के लिए उप–मिशन (एसएमएसपी)

योजना का लक्ष्य
इस योजना की मदद से सरकार निम्मलिखित लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है। इस योजना की सहायता से सरकार सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड के उत्पाद को देश में बढ़ाना चाहती है और खेती करने के लिए बचाए गए बीजों की क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहती है।
बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, परीक्षण जैसी चीजों से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों (technologies and methodologies) को बढ़ावा देना। बीज उत्पादन, भंडारण, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी आदि के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और सही करना चाहती है।
योजना का बजट - बीज और रोपण सामग्री के लिए उप-मिशन (एसएमएसपी) योजना के लिए सरकार ने 920.6 करोड़ रुपए का बजट तय किया है ।

6.कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन

योजना का लक्ष्य
इस योजना का उद्देश्य छोटे और मार्जिनल किसानों तक फार्म मशीनीकरण - को पहुंचाना है ताकि इसके इस्तेमाल से कृषि कार्यकर्ता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके।
इसके अलावा फार्म मशीनीकरण को उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाना है जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है। इस योजना से सरकार व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual Ownership) की उच्च लागत में कमी लाने के लिए कस्टम भर्ती केंद्रों का प्रचार और हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्रों का निर्माण करेगी और स्टेकहोल्डर्स के बीच अवेयरनेस पैदा करने के लिए विभिन्न नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करेगी।योजना का बजट - केंद्रीय सरकार कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन (एसएमएएम) पर 3250 करोड़ रुपए खर्च करेगी ।

7.पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन

योजना का लक्ष्य
इस योजना की मदद से सरकार फसलों पर कीड़े और अन्य कीटाणु लग जाने से होने वाले नुकसानों को कम करना चाहती है और इन कीड़े और अनचाहे पौधों, की वजह से फसलों की गुणवत्ता को भी होने वाले नुकसान को खत्म करना चाहती है ताकि फसलों की पैदावार अधिक हो सके। इस योजना का अगला लक्ष्य पौधों की सुरक्षा रणनीतियों के संबंध में विशेष रूप से अच्छे कृषि तकनीक को बढ़ावा देना है। ताकि किसान अपनी फसल को कीड़ों से बचा सके। इस योजना की मदद से सरकार वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात को सुविधा जनक बनाना चाहती है ताकि कृषि वस्तुओं का आसानी से निर्यात किया जा सके। योजना का बजट - पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव के उपमिशन (एसएमपीपीक्यू) के लिए सरकार ने 1022.67 करोड़ रुपए का बजट तय किया है ।

8.कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना

योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य कृषि जनगणना और प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करना है और देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोध, फसल को बोने से लेकर उनको काटने तक की पदानुक्रमित सूचना प्रणाली (hierarchical information system) और कृषि स्टेटिस्टिक्स कार्यप्रणाली में सुधार करना भी है।
इस योजना के तहत अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले सम्मेलनों, सेमिनार, और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए फंड देना भी है। योजना का बजट - कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना के लिए कुल 33,26 9.9 76 करोड़ रुपए में से 730.58 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

9.कृषि सहयोग के लिए एकीकृत योजना

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य वित्तीय सहायता की मदद से कोऑपरेटिव की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना है। कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण में सहकारी विकास में तेजी लाना है। कपास किसानों को उनके कपास के लिए सही मूल्य दिलवाना है और डेंटरलिज़्ड वीवर्स को भी सही मुल्यों पर गुणवत्ता संपन्न रूई की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
योजना का बजट - कृषि सहयोग के लिए एकीकृत योजना के लिए केंद्रीय सरकार ने 1902.636 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

10 कृषि विपणन पर एकीकृत योजना

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव और नई प्रौद्योगिकी और विकल्पों को बढ़ावा देना है।
ग्रेडिंग, स्टैंडर्डजेशन और कृषि उपज के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रदान करवाना है। इस योजना का जो अगला लक्ष्य है वो राष्ट्रस्तर पर मार्केटिंग सूचना नेटवर्क को स्थाइत्व प्रदान करना है और बाजार को एकीकृत करने के लिए ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा देना है।
योजना का बजट - एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इस योजना पर सरकार का कुल खर्चा 3863.93 करोड़ रुपए का आएगा।

11 राष्ट्रीय ई– गवर्नेंस (एनईजीपी – ए)

योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य कई तरह के कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों के लिए केन्द्रीयता और सेवा अभिविन्यास (centricity & service orientation) को लाना है। विस्तार सेवाओं की पहुंच और प्रभाव, किसानों की सेवाओं में सुधार, केंद्र और राज्यों की मौजूदा आईसीटी पहल को बढ़ाना और एकीकृत करना है। इसके अलावा समय समय पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाना भी है।
योजना का बजट- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (एनईजीपी-ए) मिशन के लिए सरकार ने कुल 211.06 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और ये बजट साल 2020 तक के लिए है। मोदी गवर्नमेंट ने किसानों के विकास और उनकी इनकम को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने किसानों से जुड़ी (यहां बताई गई) सभी योजनाओं की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। ताकि सरकार जल्द से जल्द किसानों का विकास कर सके और उनकी मदद इन स्कीम के जरिए कर सके।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मृदा परीक्षण से लाभान्वित हो रहे किसान

घर पर ही मिल रही जांच रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

खेतों की पैदावार हमारी आर्थिकी को तय करती है। यानि खेतों की मिट्टी यदि पोषक तत्वों से भरपूर हो तो खेतों से हम मनचाही फसलें उगा सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसानों को अभी भी खेतों की मिट्टी में पोषक तत्वों के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है। करीब 90 फीसदी किसान ऐसे हैं जो मृदा का परीक्षण नहीं कराते हैं। मृदा परीक्षण के महत्व की जानकारी न होना, मृदा परीक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव होना जैसी समस्या इसका बड़ा कारण है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के अंतर्गत गांव में किसानों को मृदा जांच के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए किसानों से गांव में जाकर जानकारी दी जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। मिशन रीव के कृषि प्रभाग के तहत विभिन्न गांवों में किसानों से बात की जा रही है। किसानों और बागवानों से बात कर पता चला कि लोग अपने खेतों में मिट्टी की जांच करवाने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उन्हें न तो जांच के लिए मिटट्ी के नमूने लेने के तरीकों की सही जानकारी है और न ही जांच करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने का वक्त।

इसे देखते हुए मिशन रीव किसानों और बागवानों को मिट्टी जांच के महत्व के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें जांच की सुविधा भी घर-द्वार पर मुहैया करवा रहा है। हाल ही मे शिमला के ठियोग ब्लॉक के तहत आने वाले थरोग व आसपास के गांव में किसानों और बागवानों को मृदा जांच एवं रीव जैविक खाद की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि हम खेतों में किस प्रकार बिना मृदा जांच के ही फसलें उगाते हैं जिससे इसकी गुणवत्ता पर तो अंतर पड़ता ही है साथ ही सही फसल के न लगाने पर परिणाम भी सही नहीं होते हैं। मृदा जांच में यह पता लग जाता है कि खेत को किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है और किस प्रकार की फसलें खेत में लगानी होगी। दशैया गांव के नरेश नगरैक व प्रमोद नगरैक, झाल्टा गांव महेंद्र सिंह झाल्टा व ठियोग के नरेश भंडारी अन्य को मिट्टी जांच के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही इनके खेतों की मिट्टी जांच भी की गई। इन सभी ने घर पर ही सुविधा देने के लिए मिशन रीव का धन्यवाद किया।

दरअसल, मिशन रीव के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव और खेत-खेत में मृदा जांच करवाने के लक्ष्य के अंतर्गत शिमला ज़िले के विभिन्न गांवो में मृदा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच की सुविधा और अन्य जानकारियां प्रदान की जा रही है। इसी के तहत शिमला ज़िले के जुब्बल, ठियोग, चौपाल आदि क्षेत्रों के विभिन्न गांवो में किसानों के खेतों से मृदा जांच हेतु शिविर आयोजित किये गए।

किसानों ने अपने खेतों एवं बागीचों की मिट्टी को जांच के लिए दिया तो रीव मृदा जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल लगातार कीटनाशकों एवं अज्ञानतावश रासायनिक खादों के उपयोग के कारण मिट्टी में बहुत से अतिआवश्यक पोषक तत्वों की कमी अथवा अत्यधिकता पाई गई है। इस असंतुलन के कारण पैदावार प्रभावित हुई हैं और फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि जागरुक किसान तीन प्रकार के ही मुख्यतः मृदा जांच को करवाने के लिए कहते है जबकि तीन टैस्ट के अलावा भी कुछ अन्य तत्वों की जांच आवश्यक होती है।

मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों ?

(1) फसलों से अधिक उपज लेने के लिये यह जानना जरूरी हो जाता है कि मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ?

(2) फसल के अनुरूप जैविक खाद, उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग।

(3) खेत की मिट्टी कौन-कौन सी फसल के लिये उपयुक्त है।

(4) मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता (पी.एच.) विद्युत चालकता का स्तर जानने के लिए।

(5) लक्षित उत्पादन प्राप्त करने एवं उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता में वृद्धि के लिये।

(6) समस्याग्रस्त, अम्लीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी के सुधार हेतु।

मिट्टी का नमूना कैसे लें

1. जिस खेत में मिट्टी का नमूना लेना हो उसमें अलग-अलग से बारह बिंदुओं/जगहों का चुनाव करें।
2. चुने गये बिंदुओं/स्थानों की उपरी एक-दो सेमी. सतह साफ करके घास, पत्थर, कचरा आदि हटा दें।

3. खुरपी की सहायता से चुने गये स्थानों में ट आकार का 6–8 इंच गहरा काट लगाकर मिट्टी को तसला या बाल्टी में रखते जायें।
4. खेत से लायी गई मिट्टी को साफ फर्श के ऊपर अखबार पर बिछाकर छाया में सुखा लें।
5. मिट्टी से घास, गोबर, पत्थर के टुकड़े फसल अवशेष निकालकर फेंक दें व मिट्टी को भुरभुरी बना लें।
6. मिट्टी के ढेर को लगभग 3 इंच की ऊचांई में गोलाकार रूप देकर चार बराबर भागों में बॉटकर आमने- सामने की दो भाग मिट्टी हटा दें। शेष दो भाग को मिलाकर इसे भी चार भागों में बॉटकर दो आमने - सामने के भाग अलग करें। ऐसा तब तक करें जब तक शेष दो भाग की मिट्टी (500 ग्राम) आधा किलोग्राम के लगभग हो जाये।
7. साफ थैली में शेष आधा किलोग्राम मिट्टी भरकर धागा से बांध दें।
8. दूसरी नई थैली में मिट्टी वाली थैली, जानकारी सहित नमूना पत्रक रखकर धागे से थैली को बांध दें।

अब आपका यह मिट्टी नमूना जांच के लिए तैयार है।

मिट्टी का नमूना कब लें ?

गर्मियों में रबी फसल की कटाई के बाद से लेकर खरीफ की बुवाई के पहले तक।

जहां लगातार पूरे वर्ष फसलें ली जाती है वहां कटाई के तुरंत बाद।

बहुवर्षीय/खड़ी फसल में पौधों की कतार के बीच से मिट्टी का नमूना लें।

मिट्टी नमूना लेने के लिए सामग्री खुरपी या आगर, तसला या प्लास्टिक की साफ बाल्टी, एक किग्रा. की दो साफ थैली, धागा, सादा कागज, साफ पुराना अखबार।

सावधानियां –

मिट्टी नमूना लेने के पहले निम्नलिखित सुझावों पर **अवश्य ध्यान दें–**

वृक्ष और देसी खाद के ढेर के नीचे की मिट्टी न ले।

खेत के कोनों एवं मेड़ से एक मीटर अंदर के ओर की मिट्टी न लें।

अधिकतर समय पानी भरे रहने वाले एवं नाली के पास के स्थान से मिट्टी न लें।

खेत की मिट्टी यदि अलग-अलग है तो नमूना की मिट्टी अलग-अलग लें।

उर्वरक, खाद, नमक की बोरी के ऊपर मिट्टी नमूना न सुखाएं।

खेत की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाये जाने वाले कंकड़ आदि अलग न करें।

यदि खेत की ढलान अधिक हैं और फसल अलग-अलग हैं तो मिट्टी का नमूना भी अलग-अलग लें।

एच्छिक जानकारी नमूना पत्रक में भरकर मिट्टी के साथ अवश्य भेजें।

अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के खेत से एक नमूना लें।

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

जांच के लिए नमूने की गहराई :–

(a) फसलों के लिए करीब 15 सेंटीमीटर

(b) बगीचों के लिए 1–3 फीट की गहराई से लेना है।

पूसा एस टी ऍफ आर मीटर किट निम्नलिखत मानको पर मिट्टी परिक्षण करती है

1	जैविक कार्बन	(OC)	8	प्राप्य आयरन	(Fe)
2	प्राप्य नाइट्रोजन	(N)	9	प्राप्य मैंगनीज	(Mn)
3	प्राप्य फास्फोरस	(P)	10	कॉपर	(Cu)
4	प्राप्य पोटैशियम	(K)	11	विद्युत चालकता	(EC)
5	प्राप्य जस्ता (जिंक)	(Zn)	12	पीएच	(pH)
6	प्राप्य सल्फर	(S)	13	एसिड मिट्टी के लिए चुना टेस्ट	
7	प्राप्य बोरोन	(B)	14	क्षारिक मृदा के लिए जिप्सम टेस्ट	

जांच शुल्क 700/– केवल मात्र **मिट्टी की रिपोर्ट 20–25 दिन**

For Details Contact : 0177 2844073, 78760 52696, 82196 94079, 98167 41687

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006 Email : info@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा

प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.

द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021
E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

मिशन रीव अब जनरल इंश्योरेंस में देगा सेवाऐं

एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के साथ होगी भागीदारी

द रीव टाइम्स

मिशन रीव अपने महत्वपूर्ण अनुभागों के माध्यम से ग्रामीण सेवाओं में निरंतर प्रयासरत है। इसमें लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्वयं व परिवार के भविष्य को उज्जवल करने के लिए मिशन रीव द्वारा एल आई सी के साथ मिलकर जीवन बीमा क्षेत्र में सेवाऐं दी जा रही है। अब मिशन रीव में एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी लोगों तक पहुंचने की सफल कोशिश की गई है। लोगों को उनके घरद्वार पर ही सेवाओं को ले जाने के लिए मिशन रीव आज सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। जीवन बीमा के क्षेत्र में दी गई सेवाओं के साथ अब लोगों को जनरल बीमा की उपलब्धता गुणवत्ता के साथ दी जा रही है।